RAJHIN/2016/70516 Bhilwara/171/2026-2028

सच्चाई से रूबरू

smarthalchal.com

स्मार्ट हलचल

वर्ष-10 अंक-226 जयपुर, गुरुवार, 12 फरवरी 2026 मूल्य-4 रूपये

वित्तमंत्री दीया कुमारी ने पेश किया 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट

'संकल्प से सिद्धि' राजस्थान का बजट

■ किसानों के लिए 11,300 करोड़ ■ पेयजल के लिए 6800 करोड़ ■ ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर की घोषणा

राजस्थान सरकार ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह बजट सदन में प्रस्तुत किया, जो भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है और दीया कुमारी का लगातार तीसरा बजट भाषण. बजट की मुख्य थीम 'विकसित राजस्थान @2047' है, जिसे 'संकल्प से सिद्धि' के नारे के साथ तैयार किया गया है. यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है. सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाना और आम जनता की जीवन स्तर सुधारना है.

जयपुर

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये बजट आकार वाला भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित रहा।

सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार बढ़ाना और आम जनता की जीवन स्तर सुधारना है। उपमुख्यमंत्री ने बताया पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश के अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 26-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड रुपए अनुमानित होने की संभावना है। करीब 2 घंटे 55 मिनिट तक चले बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, स्कूली स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने परीक्षाओं के लिए नई राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया। उन्होंने बताया सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें भी अब राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं

राजस्थान में पर्यटन विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। जैसलमेर से लेकर भरतपुर और शेखावाटी तक अलग-अलग क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। जैसलमेर के खुड़ी क्षेत्र में अल्ट्रा लक्जरी स्पेशल जोन बनाया जाएगा। कुलधरा में स्पेशल सेंटर विकसित होगा। पश्चिमी राजस्थान के शहरों को जोड़कर 'थार सर्किट' बनाया जाएगा, जिससे रेगिस्तानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खाटू श्याम और पुष्कर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। त्योहारों के अवसर पर विशेष आरती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिन पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बृज कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। शेखावाटी की हवेलियों के विकास और संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की स्थापना होगी। लोकनृत्यों को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे। महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों और गाइड की नियुक्ति की जाएगी। इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए सीकर, झुंझुनूं और डीग में एयरपोर्ट बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में हवाई सेवाओं से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

चार जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग

जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, जबकि कुलधरा में नया पर्यटन केंद्र स्थापित होगा। इसके साथ ही पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों को जोड़ते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, जिससे डेजर्ट टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भरतपुर में बृज कन्वेंशन सेंटर और झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही देवस्थान विभाग की जमीनों पर बीओटी आधार पर नई धर्मशालाएं बनाई जाएंगी।

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नई योजनाओं की घोषणा

राज्य सरकार ने गंभीर मरीजों और दुर्घटना के मामलों में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'राज सुरक्षा' नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए प्रमुख हाईवे पर स्थित रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी।

मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस

आत्महत्याओं की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 'राज ममता' नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मेंटल हेल्थ का नया सेंटर खोला जाएगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग के लिए काउंसलर भेजे जाएंगे। हर ग्राम पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।

चिकित्सा ढांचे का विस्तार

जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में 75 करोड़ रुपये की लागत से नया आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा और नियोनेटल के लिए नया आईसीयू स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 1000 नए पदों का सृजन किया जाएगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए फायर सेफ्टी उपकरणों पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मरीजों और परिजनों के लिए सुविधाएं

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनाई जाएंगी, जिन पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के पार्थिव शरीर को घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए 'मोक्षवाहिनी योजना' शुरू की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा सरकार का फोकस

राजस्थान में सड़कों का ढांचा सुधारने के लिए सरकार 1800 करोड़ की लागत से नए ब्रिज और सड़ब बनाएगी। नॉ पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक्सीडेंट रोकने 100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगाए जाएंगे।

पानी की समस्या से निपटने का प्लान

राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर 4500 करोड़ खर्च होंगे। करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होंगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।

सभी संभाग मुख्यालय होंगे सिग्नल फ्री

बजट में सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों को चरणबद्ध तरीके से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। विभिन्न विकास कार्यों पर जयपुर के लिए प्रस्तावित 1000 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए कुल 2300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। करीब 28 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। शहरी निकायों में 5000 से अधिक नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। अजमेर और जयपुर सहित अन्य शहरों में ड्रेनेज कार्यों पर 1020 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 93 फायर बाइक उपलब्ध कराई जाएंगी, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही, शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड का गठन किया जाएगा।

एआई से होगी बिजली की मॉनिटिरिंग

प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, , 132 केवी के 13 जीएसएस , 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेटर को एआई से जोड़ा जाएगा

जादुई पिटारे पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी सरकार , 323 करोड़ का खर्च होगा।

राजस्थान सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल, बिजली और शहरी विकास को प्राथमिकता दी है। सड़कों, ब्रिज, जल योजनाओं, सोलर पार्क, सिग्नल-फ्री शहरों और आवास निर्माण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की गई है।

10वीं-12वीं के बच्चों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे ई-वाउचर

दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल किट व जादुई पिटारा दिया जाएगा। इस पर 323 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही बड़ी संख्या विद्यालयों को क्रमोनत करने की घोषणा की है। कक्षा 10वीं-12वीं के होनहार विद्यार्थियों को अब लैपटॉप के लिए ई-वाउचर के माध्यम से बीस हजार दिए जाएंगे। प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को स्कूली गणवेश के लिए ढाई सौ करोड़ बजट प्रावधान की घोषणा की है। बालिकाओं को दी जाने वाली साइकिल वितरण को लेकर भी डीबीटी वाउचर की घोषणा की गई। 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में एक लाख युवाओं को 10 लाख तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा मारजीन मनी अनुदान आदि की सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6.10 लाख करोड़ का बजट पेश, 3.69 प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में आम बजट पेश किया। सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट आकार प्रस्तावित किया है, जिसे विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन के साथ तैयार किया गया है। बजट प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 5 लाख 25 हजार 740 करोड़ 34 लाख रुपये रहने का अनुमान है। वहीं, राजस्व व्यय 3 लाख 50 हजार 50 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपये आंका गया है। सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए राजकोषीय घाटा 79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.69 प्रतिशत होगा। आर्थिक प्रगति के संकेत देते हुए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने 'विकसित राजस्थान @2047' की परिकल्पना को आधार बनाते हुए पूंजीगत व्यय और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाई है।

अरावली बचाने 130 करोड़ खर्च होंगे

अरावली के 4000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार, जलसंरचना और बीजारोपण किया जाएगा। अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इस पर 130 करोड़ का खर्च होगा, वन भूमि के बदले ली जाने वाली जमीन के लिए 1000 करोड़ का लैंडबैंक बनेगा। वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए 1000 करोड़ का लैंडबैंक बनाया जाएगा। इससे परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली वन भूमि की जमीन के बदले दूसरी जमीन देकर मंजूरियां आसानी से मिल जाएंगी। इससे विकास की परियोजनाओं का काम तेज होगा। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सभी जिलों में पर्यावरण फ्रेंडली दाह संस्कार के लिए सेंटर बनेगा। कार्बन क्रेडिट रेटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली

बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। बीसलपुर के दायीं मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ मिलेगा। अगले साल 50 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे, 1500 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 8000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36 हजार नए फार्म पोंड बनाने के लिए अनुदान मिलेगा, 80 हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। 50 हजार किसानों को तारंबदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारंबदी के लिए किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाएगा। 3496 पंचायतों में वर्मी कपोस्ट यूनिट बनाई जाएंगी।

सरकारी कर्मचाारियों के लिए बड़ी घोषणा

8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकार दफ्तर बनाने, 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे। ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे , अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं हैं। मुख्य सचिव दफ्तर में डिरेगुलेशन सेल भी बनाई जाएगी। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा। शहरों में होमगार्ड की नफरी 5000 तक बढ़ाई जाएगी, इससे होमगार्ड को ज्यादा काम मिलेगा। उपनिवेशन विभाग खत्म होगा, उपननिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय होगा। गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़कर 7 करोड़ किया जाएगा। बेहतरीन काम करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार की तर्ज पर स्टेट पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे।

ये बजट खुशहाली का गारंटी कार्ड, कांग्रेस को कुछ बोलने का हक नहीं: सीएम

जयपुर

राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता के जरिये इसे 'विकसित राजस्थान विजन 2047' को धरातल पर उतारने वाला ऐतिहासिक बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली का 'गारंटी कार्ड' है और राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्पष्ट विजन और एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है. बजट का केंद्रबिंदु 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र है, जिसके माध्यम से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है. कांग्रेस के आरोपों पर सीएम भजनलाल ने कहा कि जिस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा लम्बे समय शासन किया और देश का विकास में कुछ नहीं किया. उन्हें कुछ बोलने का हक़ नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करते हैं.

10 संकल्प आधारित बजट

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों पर आधारित है. इसमें गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की गई 392 घोषणाओं में से बड़ी संख्या को दो वर्षों में पूरा कर दिया है. पिछले बजट की 86 प्रतिशत घोषणाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ योजनाओं को पूर्ण होने में समय लगता है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक शासन किया और अपेक्षित कार्य नहीं किए, उन्हें वर्तमान सरकार की नीयत और नीतियों पर प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है.

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

युवाओं को बजट का प्रमुख केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही निजी क्षेत्र में दो लाख रोजगार सृजित किए गए हैं. सरकार की नीति केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की है. इसी उद्देश्य से युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार देगी. इससे स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश में उद्यमिता का वातावरण मजबूत होगा. कौशल विकास और रोजगार नीति को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है ताकि युवाओं की क्षमताओं का समुचित विकास हो सके.

किसानों के हित में

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 10,900 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है. किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. जल संसाधनों के विकास के लिए डुक्क-तन्नरू योजना में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने कहा कि 'हर खेत को पानी' के लक्ष्य की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है. सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण और ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का नया टॉवर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं और इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

अरुणाचल और सिक्किम में लगे भूकंप के झटके, सो रहे लोगों में मचा हड़कंप

-तीव्रता 3.1 मापी गई, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वोत्तर भारत के दो राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब लोग रात की गहरी नींद में थे तब जमीन हिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जान-माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में देर रात करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। अरुणाचल के कुछ घंटों बाद ही सिक्किम के नामची में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर लोग धरती हिलने से जाग गए। यहां भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर केवल 5 किमी की गहराई पर था। बता दें धरती के नीचे होने वाली हलचल ही भूकंप का मुख्य कारण है। हमारी धरती चार परतों से बनी है, जिनके ऊपर टैक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स हर साल अपनी जगह से 4-5 मिमी खिसकती हैं। खिसकने के दौरान जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा ही भूकंप के रूप में सतह को हिला देती है। बता दें भूकंप के झटके महसूस होते ही तुरंत घर से बाहर किसी खुले मैदान में निकल जाएं। यदि बाहर निकलना मुमकिन न हो तो किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग सीढ़ियों का प्रयोग करें लिफ्ट का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। बिजली के खंभों, पेड़ों और कांच की खिड़कियों से दूर खड़े हों।

देहरादून में आईएमए के पास विवादित जमीन पर सियासी तकरार तेज

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून के धौलास इलाके में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) के पास करीब 20 एकड़ जमीन को लेकर नया विवाद उभरा है। इस जमीन को कथित तौर पर एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आवंटित किया गया था। अब बताया जा रहा है कि यह जमीन छोटे-छोटे रिहायशी प्लॉट में बांटी जा रही है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम करती। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मामला 2004 का है, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। उनका तर्क है कि इसके बाद भाजपा कई बार सत्ता में रही और इसे रोक सकती थी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह मामला कांग्रेस की खतरनाक साज़िश को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तिवारी सरकार के दौरान दी गई जमीन हरीश रावत की देख-रेख में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित थी। चमोली ने यह भी कहा कि अब जमीन पर लैंड माफिया कब्ज़ा कर रहे हैं। विकासनगर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार की शुरुआती जांच में पाया गया कि जमीन को रिहायशी प्लॉट में बदलने से आईएमए की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। जमीन विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गरमा गया है। सरकार ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि कांग्रेस इसे पुराना मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारी कम करती दिख रही है।

रामपुर में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस फोर्स तैनात

रामपुर (एजेंसी)। शहजादनगर के तहसील सदर क्षेत्र में कृषि भूमि गाटा संख्या 198 पर अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस भूमि के काश्तकारों और कुछ प्लाटिंग एजेंटों ने भूमि को आकर्षक घोषित किए बिना अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। भूमि को आकर्षक घोषित करने के लिए उप जिलाधिकारी न्यायालय में शक्कन खां आदि बनाम सरकार के अंतर्गत मामला दायर किया गया था, जिसे तीन नवंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सिविल लाइंस निवासी इमरान खां ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवैध निर्माण की शिकायत की। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई। शहजादनगर थाने की पुलिस ने मौके पर तैनाती कर नियंत्रण किया।

गड्ढे में गिरे युवक के मुंह और नाक में भर गई मिट्टी, दम घुटने से गई जान?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम से जुड़े शुरुआती निष्कर्ष में युवक कमल ध्यानी की मौत का कारण ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौत की असल वजह की पुष्टि आधिकारिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कमल ध्यानी बाइक लेकर गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में मौजूद मिट्टी उसके मुंह और नाक में चली गई, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और दम घुट गया। इसके अलावा, छाती पर भारी दबाव के संकेत भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वाहन या वस्तु के गिरने से यह दबाव पड़ा हो सकता है। पोस्टमॉर्टम में मृतक की दाहिनी जांघ पर जलने के निशान भी पाए गए हैं। डॉक्टरों का अनुमान है कि यह निशान बाइक के साइलेंसर के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण बने होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह मामला दुर्घटनावश मौत का प्रतीत होता है, लेकिन मौत के समय और तरीके को लेकर अंतिम राय गहन जांच के बाद ही दी जाएगी। इस बीच, जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सीवर लाइन बिछाने का ठेका पाने वाली निजी कंपनी के मैनेजर को हादसे की जानकारी थी, लेकिन उसने भी पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों को इसकी सूचना नहीं दी। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक वह इस मामले में हादसे की जानकारी रखने वाला छठा व्यक्ति था। पुलिस पहले ही ठेकेदार हिमांशु गुप्ता, सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति, मजदूर योगेश, सुरक्षा गार्ड देशराज और राहगीर विपिन सिंह की भूमिका की पहचान कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक एक फोन कॉल में प्रजापति ने कंपनी के डायरेक्टर हिमांशु और प्रोजेक्ट मैनेजर को हादसे की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी गई। इस मामले में राजेश कुमार, प्रजापति और योगेश को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वीर सावरकर को यदि दिया गया भारत रत्न तो इससे सम्मान की गरिमा होगी कम : भाई जगताप

-संघ प्रमुख के बयान को लेकर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ प्रमुख द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर आरोप रहे हों, उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान देना भारत रत्न की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा होगा।

भाई जगताप ने कहा कि भारत रत्न केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि अब तक यह सम्मान उन्हीं महान व्यक्तित्वों को दिया गया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र या किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। ऐसे में विवादित नामों को इस श्रेणी में शामिल करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। संघ प्रमुख किसी संगठन के प्रमुख हैं, पूरे देश के नहीं। वीर सावरकर को लेकर समाज में मतभेद और गंभीर आरोप मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें यह सम्मान देना पूरे देश में बहस और सवाल खड़े करेगा। भाई जगताप ने कहा कि यदि इस तरह के नामों को भारत रत्न दिया जाता है, तो सम्मान की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा और देश इसका मूल्यांकन करेगा।

मौजूदा सरकार में कई दागी मंत्री

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं, जिन पर दाग होने की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान पर फैसला लेना बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को बेवजह हवा नहीं देना चाहते, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा और जनता अपना जवाब जरूर देगी।

संघ प्रमुख के एक कार्यक्रम में अभिनेता की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाई जगताप ने कहा कि खेल और कला को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। उन्होंने देश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कलाकारों को धमकियां मिल रही हैं और संगठित अपराधियों में कानून का डर नजर नहीं आता। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड पर काबू पाया गया था, लेकिन मौजूदा हालात फिर चिंता पैदा कर रहे हैं।

तीन बच्चों वाला बयान हास्यास्पद

संघ प्रमुख के तीन बच्चों वाले बयान को लेकर भाई जगताप ने इसे हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तब इस तरह की सलाह देना गैर-जिम्मेदाराना है। आज महिलाएं पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं और युवा खुद यह तय करने में सक्षम हैं कि उन्हें कब और किससे विवाह करना है।

संसद में चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण

अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भाई जगताप ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, यदि कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने संसद के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि संसद देश का पवित्र मंदिर है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता। चीन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उन्हें दबाने का प्रयास करना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : एसआईटी ने तेज की जांच टीना अंबानी को जल्द मिलेगा ईडी का नया समन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही नया समन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं। सूत्रों के अनुसार, अब उन्हें दोबारा बुलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई अनिल अंबानी और उनके व्यापारिक समूह से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। यह एसआईटी फेडरल जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट के तहत काम कर रही है, जिसका नेतृत्व एडिशनल डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी कर रहे हैं। इस टीम में लगभग आधा दर्जन अनुभवी जांचकर्ता शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी समूह के खिलाफ चल रहे मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया था कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम बनाई जाए। जांच एजेंसी पिछले एक साल से इस समूह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। अब तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी हैं, जो पुलिस की प्राथमिकी के समान होती हैं। अब तक की कार्रवाई में जांच एजेंसी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है। सूत्रों का कहना है कि नवनियुक्त एसआईटी आने वाले दिनों में समूह की कंपनियों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की गहराई से पड़ताल करेगी। इस दौरान कई अन्य नई रिपोर्ट दर्ज होने की भी संभावना है, जिससे अंबानी परिवार और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

पक्षियों को दाना खिलाना पड़ा महंगा, बुजुर्ग महिला पर लगा 2.27 लाख का जुर्माना

मुंबई (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी खबर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसने पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम और देश के कड़े कानूनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मामला सिंगापुर का है, जहां एक 71 साल की बुजुर्ग महिला को बार-बार जंगली पक्षियों, विशेषकर कबूतरों को दाना खिलाने के कारण भारी-भरकम आर्थिक दंड भुगतना पड़ा है। यह खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जहां कुछ लोग इसे कानून की अति मान रहे हैं, वहीं कई लोग सार्वजनिक स्वच्छता और नियमों के पालन के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं।

पूरा मामला सिंगापुर की निवासी सन्मुगमनाथन शमला से जुड़ा है।

अदालत ने उन पर 3,200 सिंगापुर डॉलर, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2 लाख 27 हजार रुपये होते हैं, का जुर्माना लगाया है। महिला पर यह कार्रवाई वाइल्डलाइफ एक्ट के उल्लंघन के तहत की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने अदालत में अपने ऊपर लगे चार आरोपों को स्वीकार कर लिया, जबकि इसी तरह की पांच अन्य घटनाओं को भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संज्ञान में लिया गया। प्रशासन का तर्क है कि जंगली पक्षियों को इस तरह दाना खिलाने से न केवल इलाके में गंदगी फैलती है, बल्कि इससे पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है और पक्षियों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। हैरानी की बात यह है कि यह महिला के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई नहीं थी। इससे पहले मई 2025 में भी उन्हें इसी कृत्य के लिए 1,200 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा था। उस दौरान महिला ने अदालत में भविष्य में ऐसा न करने का लिखित वादा भी किया था। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड और सबूतों के अनुसार, उन्होंने अपने वादे को दरकिनार करते हुए महज एक महीने के भीतर फिर से पक्षियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया।

ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन, भगवान राम से ज्यादा ओवैसी का नाम लेते हैं

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भगवान राम से भी ज्यादा अहमियत देती है और चुनाव जीतने के लिए ओवैसी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ही बीजेपी के असली लाइफलाइन हैं। रेड्डी ने कहा कि यह बीजेपी का इतिहास है। अगर आप इसे एनालाइज करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान हैं, असदुद्दीन ओवैसी। वे यूं ही भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन वे हर दिन जिसके आगे झुकते हैं, वह असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनकी लाइफलाइन असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए वे कितनी बार राम को याद करते हैं और कितनी बार ओवैसी का नाम लेते हैं। इसकी पड़ताल होनी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ओवैसी को अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बार वे ओवैसी को अलादीन का जादुई चिराग बनाकर वोट मांगते हैं। आखिर सरकार तो आपकी ही है ना? अगर ओवैसी इतने विलेन हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रेड्डी ने एआईएमआईएम की निंदा के लिए भी बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में एआईएमआईएम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। जहां वे जीतते हैं, जीतते हैं। जहां वे हारते हैं, हारते हैं। उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां तक ??कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने पांच सीटें जीतीं हैं। वे भी एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन आप कब तक उनके नाम पर वोट मांगते रहेंगे? धार्मिक नफरत भड़काकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को राक्षस बताकर और उसके जरिए पॉलिटिकल रूप से जिंदा रहने की कोशिश करना आइडियोलॉजिकल गरीबी की हद है। तेलंगाना के लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए।

एसआईआर के दौरान हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

-पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकियों का मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्यूटी के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ कथित हिंसा और धमकियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे पर जवाब न देने को लेकर डीजीपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

अदालत ने यह निर्देश उस समय दिया, जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने पीठ का ध्यान चुनाव आयोग के हलफनामे की ओर दिलाया। इस हलफनामे में पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं, धमकियों और हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने दावा किया है कि राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में भय और दबाव का माहौल कहीं अधिक है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में डराने-धमकाने, बाधा डालने और भ्रामक सूचनाएं फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं। हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी भड़काऊ भाषण देने और भय का वातावरण बनाने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस तरह के बयानों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जलाए गए। इसके अलावा, पंचायत भवनों में सुनवाई के लिए पहुंचे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ हिंसा की घटनाएं हुईं। आयोग के अनुसार, कई अधिकारियों को लोकतांत्रिक दायित्व निभाते समय अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, जिससे वे भय के साए में काम करने को मजबूर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि चुनाव जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। यदि इस दायित्व में चूक हुई है, तो इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से यह बताना होगा कि चुनाव आयोग के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। अदालत ने संकेत दिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे और सख्त निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है।

सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 51 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी दोहरी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को एक विशेष अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने न केवल नक्सलियों के एक गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, रायगुडेम गांव के पास स्थित पहाड़ी जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने 65 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल और कमर पर बांधी जाने वाली दो विशेष थैली बरामद कीं। इतनी बड़ी संख्या में बीजीएल सेल की बरामदगी को सुरक्षाबल नक्सलियों की किसी बड़ी और घातक साजिश की विफलता के रूप में देख रहे हैं।

इस सैन्य सफलता के साथ-साथ बस्तर संभाग में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कामयाबी भी देखने को मिली है। सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.61 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अधिकारियों का मानना है कि नक्सलियों के इस सामूहिक आत्मसमर्पण के पीछे हाल ही में शीर्ष नक्सली नेता एल. प्रभाकर राव का खात्मा एक बड़ा कारण रहा है। अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में प्रभाकर राव और उसके छह साथियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों का मनोबल बुरी तरह टूट गया है। राव को एक खतरनाक एंबुश रणनीतिकार माना जाता था, जिसकी मौत ने नक्सली संगठन के ढांचे को कमजोर कर दिया है। बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 2,400 से अधिक नक्सली हथियार डाल चुके हैं। सरकार की पूना मारोगेम (नई राह) और नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) जैसी पुनर्वास योजनाओं का जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इन पहलों के माध्यम से प्रशासन अब उन दुर्गम इलाकों तक सीधी पहुंच बना रहा है, जहाँ कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। फिलहाल, सुरक्षाबलों ने इलाके में चौकसी और अधिक बढ़ा दी है और आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान जारी है ताकि बचे हुए नक्सलियों पर दबाव बनाया जा सके।

12 फरवरी को 35 साल बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा... भारत की पैनी नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा। इसके बाद 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पार्टी की भूमिका की वजह से यह फैसला लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश के ये चुनाव सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। इसलिए भारत, पाकिस्तान और चीन भी इन चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत के साथ रिश्ते अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हुए हैं और चीन के साथ रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिर तोड़ने और हिंसा की खबरें आने लगीं, जिस पर भारत ने चिंता जाहिर है। बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ बातें फैलीं।

भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी के बीच तनाव बढ़ा, तस्करी और बाड़ को लेकर बहस हुई। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंसा फैली और भारत के खिलाफ माहौल बना। दोनों देशों के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने आपस में सीधे बात करना शुरू किया, इससे पुराने तनाव धीरे-धीरे कम होने लगे। 2025 में कराची और चटगांव के बीच कॉर्गो जहाज फिर से चलने लगे, जिससे समुद्री व्यापार आसान हुआ। 2026 की शुरुआत में ढाका और कराची के बीच कई साल बाद सीधी फ्लाइट्स शुरू हुईं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वीजा के नियम आसान करने पर बात की, खासकर सरकारी काम से आने-जाने वालों के लिए। अंतरराष्ट्रीय बैठकों में पाकिस्तान और बांग्लादेश कई मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आए, जिससे तालमेल बढ़ा।

चीन से और करीबी बढ़ी

2025 में बांग्लादेश के नेताओं और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, जिसमें रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर खुलकर बात हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश से जुड़े समझौतों पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया। चीन ने बांग्लादेश से आने वाले ज्यादातर सामान पर टैक्स नहीं लगाने की सुविधा आगे भी जारी रखने की बात कही। रक्षा के मामले में भी दोनों देश करीब आए और ड्रोन व दूसरी सैन्य तकनीक से जुड़े समझौते किए गए। बांग्लादेश का आम चुनाव तय करेगा कि देश आगे भारत के करीब रहेगा या पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेगा। इससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग चारों तरफ से घेरता है। भारत का नॉर्थ-ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत से कनेक्ट होता है। इसके बाद बांग्लादेश की भूमिका भारत के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सप्लाई लाइनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो जाती है।

दूसरी बड़ी वजह है भारत-चीन की रणनीतिक खींचतान। चीन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर चुका है। बांग्लादेश अगर चीन के ज्यादा करीब जाता है, तब यह भारत के लिए सीधा रणनीतिक झटका होता है, खासकर बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन रीजन में। बांग्लादेश की समुद्री सीमा इस इलाके को रणनीतिक रूप से बहुत अहम बना देती है। यह इलाका ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी रूट्स और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है।

राजस्थान बजट 2026 और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

द बजट एक्सपोज : राजस्थान बजट 2026-27 विशेष रिपोर्ट

झुनझुनों का पिटारा: राजस्थान के बजट में आंकड़ों की बाजीगरी, जनता को मिला 'शून्य'

भजनलाल सरकार के तीसरे पूर्ण बजट में विकास के नाम पर केवल लोकलुभावन वादों की चाशनी घोली गई है। धरातल पर न तो निवेश है और न ही रोजगार

स्मार्ट हलचल|जयपुर

राजस्थान के बजट 2026-27 के पेश होते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई है। वित्त मंत्री ने 'विकसित राजस्थान' का जो खाका पेश किया है, वह हकीकत से कोसों दूर एक काल्पनिक दस्तावेज नजर आता है। बजट में सबसे बड़ी चिंता राजस्थान पर बढ़ता अभूतपूर्व कर्ज का बोझ है, जो अब हर राजस्थानी के सिर पर एक भारी बोझ बन गया है।

कर्ज का जंजाल: विकास के नाम पर गिरवी भविष्य

सरकारी दावा: सरकार का दावा है कि वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ है और बजट घाटा कम हुआ है।

धरातल की हकीकत: हकीकत यह है कि राजस्थान पर कुल कर्ज 7.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। प्रति व्यक्ति कर्ज में 25% की वृद्धि हुई है। विकास कार्य केवल कागजों पर हैं, जबकि ब्याज भुगतान बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा है।

आंकड़ा: कर्ज में 18% की रिकॉर्ड वृद्धि

युवा शक्ति से विश्वासघात: 'रोजगार उत्सव' के पीछे बेरोजगारी का अंधेरा

सरकारी दावा: 5 लाख नई सरकारी नौकरियों का वादा और निजी क्षेत्र में निवेश का ढिंढोरा।

धरातल की हकीकत: पेपर लीक की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। 'सीईटी' के नाम पर युवाओं को अटकाया जा रहा है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा ठंडे बस्ते में है।

आंकड़ा: बेरोजगारी दर 28% (राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक)

अन्नदाता की अनदेखी: केवल नारों तक सीमित किसान कल्याण

सरकारी दावा: कृषि बजट में भारी बढ़ोतरी और मुफ्त बिजली का दावा।

धरातल की हकीकत: स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना तो दूर, एमएसपी पर खरीद का बुनियादी ढांचा भी ध्वस्त है। फसल बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

आंकड़ा: 50% किसानों को नहीं मिला उचित मुआवजा

स्वास्थ्य सेवा का संकट: विज्ञापन में एम्स, धरातल पर रेफरल केंद्र

सरकारी दावा: हर जिले में मेडिकल कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं।

धरातल की हकीकत: पुरानी योजनाओं (चिरंजीवी) का नाम बदलकर उन्हें जटिल बना दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40% पद रिक्त हैं। आंकड़ा: ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में 45% डॉक्टरों की कमी

संपादकीय: जनता को गुमराह करने का 'मास्टरक्लास'

'बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, यह सरकार की नीयत का दर्पण होता है। बढ़ते कर्ज और घटते रोजगार के बीच राजस्थान को 'आत्मनिर्भर' बनाने का दावा एक क्रूर मजाक से अधिक कुछ नहीं है। '

बजट में चित्तौड़गढ़ को मिली 200 करोड़ से अधिक की ऐतिहासिक सौंगात: विधायक आक्या

स्मार्ट हलचल|ओम जैन

चित्तौड़गढ़। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान की भजन लाल सरकार की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश बजट की प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है।

विधायक आक्या ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया की बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा के विकास पर ध्यान दिया गया है। धनेतकलां पुलिस लाईन के पास बेड़च नदी पर पुलिया निर्माण के लिये 25 करोड़ की स्वीकृती, गाडरीखेड़ा (सतपुड़ा) से सिंहपुर वाया कंथारिया-नेतावल महाराज-बैजनाथियां-छापरी तक 19 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 40 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से विजयपुर वाया अभयपुर-पालेर-गोरसिया तक 25 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 40 करोड़, कुम्भा बॉयलाजिकल पार्क विकास हेतु 31 करोड़, पन्नाधाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य गंभीरी रिवर फ्रंट हेतु 20 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसी क्रम में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर 10 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ऐथेलेटिक ट्रेक की स्थापना व बेड़च नदी पर भोईखेड़ा से बीसीडब्लु चंदेरिया तक कॉजवे हेतु 5 करोड़, गंभीरी मध्यम सिंचाई परियोजना की बायीं मुख्य नहर की चेन संख्या 600 से टेल तक माईनरों का पुनरूद्धार कार्य हेतु 25 करोड़, हैरिटेज वॉकवे का निर्माण हेतु करीब 5 करोड़ की स्वीकृति सहित अनेक सोगाते दी गई है।

विधायक आक्या ने बजट में विधानसभा चित्तौड़गढ़ को मिली ऐतिहासिक सौंगात के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री वित्त मंत्री दीया कुमार एवं सांसद सी.पी. जोशी का आभार व्यक्त किया है।

राजस्थान सरकार का बजट सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा

स्मार्ट हलचल।भादसोड़ा

यह बजट गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण का स्तम्भ बनेगा। अर्थव्यवस्था की प्रगति, औद्योगिक विकास, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और स्वरोजगार को नया मार्ग प्रशस्त करेगा। संस्कृति, धरोहर और पर्यटन को नई ऊंचाईयां मिलेगी। यह बजट सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा।

राधे सुथार

बजट थोथी घोषणाओं का पुलिंदा:जाड़ावत

स्मार्ट हलचल

शंभूपुरा। राजस्थान सरकार के पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किये बजट को थोथी घोषणाओं का पुलिंदा बताया है, पेंशन धारियों लिए निराशाजनक बजट है।

उन्होंने कहा कि दिशा हीन बजट आज विधानसभा में पेश हुआ है बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोडमैप नहीं है, किसान को लिए बजट में विशेष कुछ नया नहीं है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पूर्व में बजट में घोषणा हुई वो भी धरातल पर नहीं आई है नई योजना किस तरह धरातल पर आएगी यह भविष्य के गर्भ में है गंभीरी रिवल फ्रंट की घोषणा में तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर इसमें गिरने वाले सिवरेज के पानी को रोकते तो यह घोषणा सार्थक होती जो 40 करोड़ की विजयपुर वाली सड़क की घोषणा हुई वो पूर्व में ही अशोक गहलोत के 23-24 के बजट में स्वीकृत हो चुकी थी वन विभाग द्वारा एनओसी भी जारी कर दी गई उसी सड़क को इन्होंने बजट में जोड़ दिया जो पूर्व में ही स्वीकृत थी। चिकित्सा क्षेत्र में सेटेलाइट हॉस्पिटल में डाक्टरों के पद खाली हैं इन्हें भरने की घोषणा नहीं हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पद रिक्त हैं। संसाधनों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। आमजन व मार्बल उद्यमियों को कुछ नहीं मिला है। बजट में केवल कागजी घोषणाएं हैं। दो साल के बजट में की घोषणाएं भी अभी पूरी नहीं हुई।

बजट विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में एक दूरदर्शी कदम

स्मार्ट हलचल|जयपुर

राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की स्पष्ट झलक देता है। इस बजट में आधारभूत संरचना को मजबूत करने, सड़क एवं परिवहन तंत्र के विस्तार, पेयजल परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा विद्युत व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में नए महाविद्यालयों, कौशल विकास केंद्रों एवं डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन, अस्पतालों में संसाधनों की बढ़ोतरी और नई स्वास्थ्य योजनाओं से आमजन को राहत मिलेगी।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए की गई घोषणाएं किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, MSME सेक्टर को मजबूती और रोजगार सृजन पर विशेष जोर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

बजट में नर्सेज को निराशा हाथ लगी

स्मार्ट हलचल

राजस्थान राज्य बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजवीर यादव दिवराला ने बताया कि राजस्थान सरकार को मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल , उपजिला अस्पताल आदि में नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए कम से कम 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा करनी चाहिए थी। क्यू की सरकार ने प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल खोले हैं जहा हजारो पद रिक्त है, सरकार से नर्सेज़ को नर्सिंग निर्देशालय व केंद्र के समान वेतन की उम्मीद थी। लेकिन नर्सिंग की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया! राजवीर दिवराला ने बताया कि इस बजट नर्सेज में भारी गुस्सा है,

राजवीर यादव दिवराला
एम्स हॉस्पिटल अजीतगढ़

शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा, हितों पर कुठाराघात – संयुक्त अभिभावक संघ

स्मार्ट हलचल|जयपुर

राजस्थान सरकार द्वारा घोषित बजट 2026 को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने गहरी निराशा एवं आक्रोश व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि यह बजट सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के बजाय निजी स्कूलों और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने वाला बजट साबित हुआ है।

संघ ने आरोप लगाया कि बजट में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधार, शिक्षक भर्ती, आधारभूत ढांचे, डिजिटल संसाधनों और विद्यार्थियों की सुरक्षा जैसे मूलभूत विषयों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। प्रदेश के लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों की वर्षों पुरानी मांगों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।

संयुक्त अभिभावक संघ के अनुसार

1) निजी स्कूलों की मनमानी फीस 2) आरटीई के तहत प्रवेश में हो रही अनियमितताएं 3) अतिरिक्त शुल्क वसूली 4) स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा एवं बुलींग की बढ़ती घटनाएं 5) एक समान एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम लागू करने जैसे गंभीर मुद्दों पर बजट पूरी तरह मौन है।

संयुक्त अभिभाषक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि यह बजट अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ किए गए अन्याय को और गहरा करता है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण और प्रोत्साहन देता है। इससे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ेगा और आम व मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ और अधिक पड़ेगा।

संयुक्त अभिभावक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निजी स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण और अभिभावक-विद्यार्थी हितैषी नीतियां लागू नहीं कीं, तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होगा। संघ ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि शिक्षा को लाभ का नहीं, सेवा का क्षेत्र मानते हुए बजट में आवश्यक संशोधन किए जाएं और प्रदेश के भविष्य यानी विद्यार्थियों के साथ न्याय किया जाए।

अभिषेक जैन बिट्टू

यातायात नियमों पर दी जागरूकता

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालना हेतु उन्नत इलेक्ट्रोनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालना हेतु उन्नत इलेक्ट्रोनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली स्थापित की जा रही है। 11.02.2026 को यातायात पुलिस, भीलवाड़ा द्वारा वाहन चालाको को ओवरस्पीड़ (निर्धारित गति सीमा से अधिक गति)से वाहन नही चलाने, हेलमेट के बिना वाहन नही चलाना, दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी नही बिठाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग नही करने, सीटबेल्ट के बिना वाहन नही चलाने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 लेन सिस्टम की पालना करने एवं गलत दिशा में वाहन नही चलाने हेतु जागरूक किया गया।

बजट युवाओं, महिलाओं व किसान वर्ग के लिए उपयोगी : मंजू जांगिड़

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिला देहात महिला मोर्चा की जिला मंत्री मंजू जांगिड़ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को युवाओं, महिलाओं एवं किसान वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है तथा हर वर्ग के उत्थान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मंजू जांगिड़ ने बताया कि छात्रों को टेबलेट, स्कूटी, साइकिल एवं यूनिफॉर्म के लिए ई-डीबीटी वाउचर देने की घोषणा सराहनीय है। गाड़िया लोहार समुदाय के बच्चों के लिए 'स्कूल ऑन व्हील्स' योजना तथा जर्जर अथवा भवनहीन विद्यालयों के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लगभग ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को अंग्रेजी, जापानी सहित अन्य विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई है।

मंजू जांगिड़ ने बताया कि बजट में सिंचाई विभाग को सुदृढ़ करने, नए पर्यटन स्थलों के विकास, धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3600 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के विकास, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग सुविधाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा नए सोलर पार्कों की स्थापना, तीव्र औद्योगिक विकास, पेयजल एवं विद्युतीकरण के ठोस उपाय भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान देने वाला है और राजस्थान को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राजस्थान सरकार का बजट 'खोखले वादों का पुलिंदा' और 'जनता के साथ छलावा' : पूर्व सहकारिता मंत्री आंजना

सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के आपसी झगड़ों में लगे रहने की वजह से चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले की आवाज विधानसभा में हुई कमजोर : आंजना

स्मार्ट हलचल|निंबाहेड़ा

पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किया गया वार्षिक बजट पूरी तरह से दिशाहीन और निराशाजनक है। यह बजट धरातल की सच्चाई से दूर, केवल आंकड़ों की बाजीगरी और चुनावी घोषणाओं का एक पिटारा मात्र है, जिसमें आम आदमी के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। आंजना ने कहां की बढ़ता कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकार राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल रही है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। बिना आय के स्रोतों पर ध्यान दिए की गई घोषणाएं केवल आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाएंगी।

बेरोजगारों के साथ मजाक एवं महंगाई रोकने में असमर्थ बजट : आंजना ने कहां की प्रदेश का युवा रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सरकार ने नई भर्तियों के नाम पर केवल पुरानी योजनाओं को नया नाम दिया है। निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और कौशल विकास के लिए कोई ठोस नीति नहीं दिखी। साथ ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर बजट पूरी तरह मौन है। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को महंगाई से कोई राहत नहीं दी गई है।

किसानों की अनदेखी सहित बुनियादी ढांचे को सशक्त करने को लेकर सरकार दिशाहीन : आंजना ने कहां की कृषि बजट के नाम पर केवल लोकलुभावन बातें की गई हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने या कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार ने एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल नई इमारतों की घोषणा की गई है, जबकि पहले से मौजूद केंद्रों में डॉक्टरों, शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी को दूर करने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।

निम्बाहेड़ा विधानसभा एवं चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ जिले को नहीं मिली आशानुरूप सौगात : आंजना ने कहां की निम्बाहेड़ा विधानसभा सहित चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके, जिस वजह से क्षेत्र की जनता में भारी निराशा है एवं इस दिशाहीन बजट के बाद प्रदेश, जिले एवं विधानसभा की जनता पुनः कांग्रेस के राज को याद करने लगी है जब बजट में प्रत्येक जिले एवं विधानसभा को उचित प्रतिनिधित्व मिलता था एवं जनता की आशा अनुरूप विकास कार्यों की सौगाते बजट के माध्यम से क्षेत्र को मिलती थी। लेकिन सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के आपसी झगड़ों में लगे रहने, विधानसभा में बार-बार खड़े होकर केवल मीडिया में खुद को जीवित रखने का प्रयास करने एवं विधायकों के जन समस्याओं को दूर करने की जगह अपने व्यापारिक हितों की सिद्धि हेतु कार्य करने की वजह से हमें बजट में विशेष स्थान नहीं मिला है जिससे क्षेत्र की जनता क्षुब्ध है।

आंजना ने कहा कि जनता जानती है कि राजस्थान सरकार पिछले 2 बजट में अपने द्वारा की गई घोषणाओं में से 30% घोषणाओं को भी पूरी नहीं कर पाई है। अब सरकार 1 बजट और लेकर आई है परंतु यह बजट भी सरकार में विजन एवं नेतृत्व की कमी को दर्शाता है। यह राजस्थान के विकास का नहीं, बल्कि केवल भाजपा के प्रचार का बजट है।

शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आने वाले समय में राज्य के विकास की रफ्तार तय करेगी: एमडी वजीरानी

स्मार्ट हलचल| ओम जैन

चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ अरबन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व निदेशक वंदना वजीरानी ने कहा कि बजट न केवल वार्षिक आर्थिक खाका है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और मानव विकास की दिशा में एक ठोस प्रयास भी है। महिलाओं, बच्चों, शिक्षा और सहकारिता पर केंद्रित यह बजट भविष्य में राज्य की सामाजिक-आर्थिक संरचना को स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा।

इस बजट का प्रमुख उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 'समावेशी विकास मॉडल' की दिशा में ले जाना है। महिला स्वयं सहायता समूहों और 'लखपति दीदी' योजना के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इससे न केवल घरेलू आय में वृद्धि होगी, बल्कि छोटे-मोटे उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र में निवेश से गांव-स्तरीय आर्थिक ढाँचा मजबूत होगा, जिससे राज्य की कुल उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, महिला उद्यमिता और सूक्ष्म-वित्तीय सहायता योजनाएँ आर्थिक स्वावलंबन का वातावरण तैयार करेंगी, जो दीर्घकाल में राज्य की जीडीपी में योगदान और सामाजिक स्थिरता दोनों को बढ़ाएँगी।

महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएँ, बालिकाओं हेतु छात्रावास और स्कूटी वितरण जैसी नीतियाँ केवल तात्कालिक लाभ नहीं देतीं, ये उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाती हैं। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की रफ्तार तय करेगी। वहीं बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य योजनाएँ भविष्य की कार्यबल को मजबूत बनाएँगी। शुरुआती उम्र में मिलने वाला बेहतर पोषण और शिक्षा उनकी उत्पादकता, सीखने की क्षमता और जीवन-गुणवत्ता पर स्थायी प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कौशल और करियर उन्मुख बनाया है। नए विद्यालयों और देव नारायण बालिका संस्थानों की स्थापना, आधुनिक तकनीकी प्रयोग और व्यावसायिक शिक्षा पर बल से ग्रामीण व शहरी छात्रों के बीच की दूरी कम होगी।

इससे आने वाले दशक में एक नई 'सक्षम और आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी' तैयार होगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार और सामाजिक भागीदारी की ऐसी बुनियाद रखी गई है जो आने वाले वर्षों में राज्य को समृद्धि, समानता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी।

जाति प्रमाण पत्र बनवाना बना आम जनता के लिए सिरदर्द, सरकार की जटिल प्रक्रिया

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र बनवाना आज आम आदमी के लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है। समाजसेवी मोहम्मद हारून रंगरेज ने जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रंगरेज का कहना है कि सरकार की तय की गई औपचारिकताएं इतनी जटिल हैं कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हताश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाता है। उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को पहले यह साबित करना पड़ता है कि वह ओबीसी जाति से है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म पर दो गजेटेड ऑफिसर के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। यही नहीं, आय प्रमाण पत्र पर भी दो गजेटेड ऑफिसर के साइन जरूरी हैं। सरकार के सामने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी दो-दो गजेटेड ऑफिसर कहां से लाए? क्या हर गरीब व्यक्ति के रिश्तेदार गजेटेड अफसर होते हैं? हकीकत यह है कि गजेटेड ऑफिसर आमतौर पर ऐसे साइन करने से बचते हैं। कई बार लोग घंटों दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, फिर भी गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं करते। इसके बाद आवेदक से पट्टा व रजिस्ट्री मांगी जाती है, फिर पटवारी की रिपोर्ट लगती है

और अंत में इन सभी दस्तावेजों पर नोटरी पब्लिक से सत्यापन कराना अनिवार्य होता है।

मोहम्मद हारून रंगरेज का कहना है कि इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी कई मामलों में 'ऑब्जेक्शन' लगा दिया जाता है और प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता। सबसे गंभीर बात यह है कि जिन लोगों का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, और उनके पिता व दादा का भी जाति प्रमाण पत्र मौजूद है, फिर भी उनका नया या संशोधित जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। वैध दस्तावेज होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा फाइल पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और दलालों को बढ़ावा दे रही है। गरीब आदमी सीधे काम नहीं करवा पाता, मजबूरी में उसे बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। राजस्थान सरकार से मांग की है कि जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। गजेटेड ऑफिसर के दोहरे हस्ताक्षर की शर्त को हटाया जाए और ऑनलाइन व पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया तो आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 4 साल कठोर कारावास व जुर्माना

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

14 वर्षीय नाबालिग को डरा धमकाकर जबरन बलात्कार करने के आरोप में दुष्कर्मी को पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सजा सुनाते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने इस मामले की पैरवी करते हुए 11 गवाह और 26 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया । प्रार्थी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कर बताया की वह डेयरी बूथ चलाता है और वह ज्यादा बीमार होने के कारण अपने काम पर ध्यान नही दे पा रहा था इस दरमियान प्रार्थी के पिता बूथ पर रोजाना बैठते है और उसकी नाबालिग 14 वर्षीय पुत्री भी बूथ पर बैठती थी इस दौरान आरोपी अब्दुल मंसूरी लगातार उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता और उसके साथ अश्लील हरकते करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी आरोपी मोबाइल नंबर मांगता था नही देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता ओर सोशल मीडिया पर उसकी पुत्री की अश्लील मैसेज करता और फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया कर नाबालिग के न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देता इसके बाद एक बार शास्त्रीनगर में बुलाकर दुष्कर्मी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । घटना के बाद पीड़िता डरी और सहमी सी रहने लगी परिजनों के कई बार पूछने के बाद भी उसने नही बताया जब एक दिन परिजनों ने प्यार से पूछा तो पीड़िता ने आपबीती बताई । जिसके बाद प्रार्थी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 4 साल कठोर कारावास और 20 हजार रु जुर्माने की सजा सुनाई।

शाहपुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान, 102 किलो जब्त

स्मार्ट हलचल | शाहपुरा

राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के निर्देशानुसार नगर पालिका शाहपुरा द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पालिका क्षेत्र के सदर बाजार, नया बाजार, वेलकम प्लाजा, त्रिमूर्ति चौराहा तथा बस स्टैंड परिसर में सघन कार्रवाई की गई।

इस दौरान पालिका टीम ने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जांच करते हुए 102 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर संबंधित व्यापारियों से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया। साथ ही व्यापारी वर्ग एवं आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

आज की कार्रवाई में पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक हेमंत पुंडरीक, जमादार विकास घूसर, सत्येंद्र कुमार, नितिन, अमित एवं संदीप सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। पालिका आयुक्त रिंकल गुप्ता ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग बंद कर कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें, ताकि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।

एमजी चिकित्सालय के कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, फूटा गुस्सा, दी आंदोलन की चेतावनी

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की अगुवाई में चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण गौड़ को सौंपा पत्र

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। जिले के सबसे बड़े राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य विभागों के कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से वेतन (सैलरी) नहीं मिला है। इस गंभीर समस्या को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक फरीद मोहम्मद रंगरेज एवं शहर अध्यक्ष लाल सिंह राठौर की अगुवाई में चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण गौड़ को सौंपे पत्र में बताया कि वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। कर्मचारियों को अपने घर का राशन, दूध, सब्जी और मकान की किस्तें चुकाने के लिए ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ रहा है। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि समय पर वेतन न देना श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और बकाया वेतन जारी नहीं हुआ, तो कर्मचारी मजबूरन कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि आगामी दिनों में कोई विरोध प्रदर्शन या कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन की होगी। इस दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनील पोरवाल सिराज खान, राजेश जोशी, रेहान अंसारी, हितेश लखारा, रामजस चौधरी और पंकज राठी और भी बहुत सारे कर्मचारी उपस्थित थे।

किसानो, युवाओं महिलाओ, मध्यम वर्ग सभी के सशक्तिकरण का मजबूत आधार है: महामंत्री जाट

स्मार्ट हलचल | ओम जैन

चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार द्वारा 11 फरवरी को प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के किसान नेता एवं सावा भाजपा मंडल के महामंत्री रामप्रसाद जाट ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी का आभार जताया।

महामंत्री जाट ने कहा कि यह बजट उन लोगों को समर्पित है जो मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखते हैं, यह बजट किसानो, युवाओ, महिलाओ, गरीबो और मध्यम वर्ग आदि सभी के सशक्तिकरण का मजबूत आधार है।

उन्होंने कहा नए विद्यालयों और देव नारायण बालिका संस्थानों की स्थापना, आधुनिक तकनीकी प्रयोग और व्यावसायिक शिक्षा पर बल से ग्रामीण व शहरी छात्रों के बीच की दूरी कम होगी। इससे आने वाले दशक में एक नई 'सक्षम और आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी' तैयार होगी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी।

किसान नेता जाट ने कहा कि यह बजट आने वाले समय मे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

तुलसी जी की लिखी लग्न पत्रिका, बारात बागोर से आएगी

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

माली समाज विकास सेवा संस्थान पुर के तत्वावधान में चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन पुर स्थित घाटी के हनुमानजी परिसर में 19 फरवरी 2026 को सम्पन्न किया जाएगा । माली समाज के चुतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन कि शुरुआत आज बुधवार को तुलसी संग सालगराम जी के लग्न से की गई। माली समाज विकास सेवा संस्थान पुर के अध्यक्ष भैरूलाल माली ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को फुलेरादोज पर आयोजित होने वाले माली समाज के चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन में भगवान सालगराम जी संग तुलसी विवाह भी सम्पन्न किया जाएगा।

इसी कड़ी में आज बुधवार को बागोर माली समाज के पंच पटेलो ने तुलसी विवाह के तहत आज विधि-विधान से चुनरी दस्तुर किया गया, तत्पश्चात् पं. अशोक शर्मा के सानिध्य में लग्न पत्रिका भी लिखी गई। उपस्थित सभी समाजजनों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में आने की निमंत्रण पत्रिका भी वितरित की गई। अब तक इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 17 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। विवाह समिति का लक्ष्य 21 जोड़ो का विवाह कराना है। इस ओर समाजजन हर तरह से प्रयासरत है। संस्था अध्यक्ष ने समाज से अपील की है कि इस सम्मेलन में सभी समाजबंधु एकजुट होकर तन-मन-धन से विवाह समिति को भरपूर सहयोग करें, ताकि इस आयोजन को भव्यता प्रदान की जा सके।

इस अवसर पर सामूहिक विवाह समिति के सचिव शंकरलाल गोयल, संरक्षक रामस्वरूप माली, तोताराम सांखला, कैलाश नुईवाल, जगदीश ढिबरिया, बंशीलाल माली, प्रभुलाल नुईवाल, बंशीलाल कनवासिया, रामेश्वर लाल माली, नानूराम गोयल, देवालाल ढिबरिया, , नारायण कनवासिया, कालू माली, लाल चंद गोयल, महावीर ढिबरिया, माली महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली, जिला महामंत्री सत्यनारायण माली, युवा महासभा जिला अध्यक्ष उदयलाल माली, सोशल मीडिया प्रभारी रोशन गढ़वाल, राजकुमार गोयल, सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित थे।

बजट शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रीय विकास इंफ्रा सौंदर्य करण और रोजगार सृजन को देगा बढ़ावा-: रिजु झुनझुनवाला

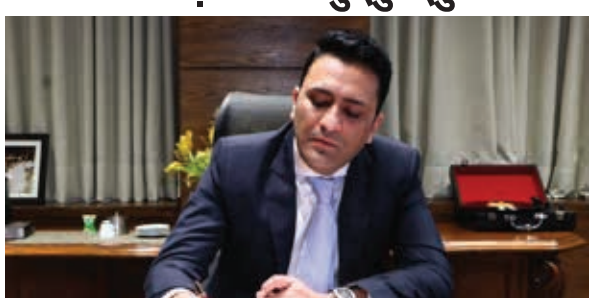

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार की बजट पर आरएसडब्ल्यूएम भीलवाड़ा ग्रुप की ओर से श्री रिजु झुनझुनवाला ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल के सफल मार्गदर्शन और वित्त मंत्री सुश्री दिया कमारी जी का आभार व्यक्त किया। यह बजट विकास ,विनिर्माण को बढ़ावा, एमएसएमई को समर्थन, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने वाला है।

श्री झुनझुनवाला ने कहा कि भीलवाड़ा, जो देश का प्रमुख कपड़ा हब इस बजट से सीधे लाभान्वित होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आधुनिक मशीनरी, बुनियादी ढांचे का विस्तार, लॉजिस्टिक्स सहायता और कौशल विकास, रोजगार सृजन से यहां की वस्त्र उपक्रम इकाइयां और मजबूत होंगी। इससे अलावा उत्पादन क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।

भीलवाड़ा में नए निवेश, मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा का उपयोग और निर्यात वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

साथ ही आज उपमुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान बजट के लिए भी श्री झुनझुनवाला ने हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे भीलवाड़ा सहित पूरे राजस्थान के औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का भी आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में सकारात्मक वातावरण, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से भी राज्य के बाहर के उद्यमियों को विनिवेश के लिए प्रोत्साहित एवं आमंत्रित भी किया गया।

श्री झुनझुनवाला ने विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से भीलवाड़ा कीड्ड टेक्सटाइल क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगा।

पिकअप से नकद राशि का बेग चुराकर ले जाने वाले 2 चोर को गिरफ्तार

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

गुलाबपुरा पुलिस साईबर सैल और डीएसटी टीम भीलवाडा ने संयुक्त रूप से बडी कार्यवाही करते हुए पिकअप से नकद राशि का बेग चुराकर ले जाने वाले 2 चोर को गिरफ्तार कर पूरी राशि बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसपी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा सम्पति संबंधी अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत एएसपी राजेश आर्य शाहपुरा के निर्दशन में व वृताधिकारी गुलाबापुरा जितेन्द्र सिंह के निकटतम सुपरविजन मे संजय कुमार थानाधिकारी, गुलाबपुरा के नेतृत्व में साईबर टीम व डीएसटी टीम भीलवाडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबीर व तकनीकी माध्यमों से अज्ञात आरोपियों का पिछा करते हुये पिकअप की केबिन से नकद राशि का बेग चुराकर ले जाने वाले आरोपी पप्पूसिंह राजपूत व भैरूलाल मेघवंशी को गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार 9.2.2025 को प्रार्थी ने थाना गुलाबपुरा पर रिपोर्ट पेश की कि मुझ प्रार्थी की कम्पनी इण्डिया जेनेटिक प्राईवेट लिमिटेड है। दिनांक 06.02.2026 को पिकअप अजमेर से भीलवाडा जा रही थी जिसमे ड्राईवर पप्पूसिंह पिता जीतसिंह राठौड व परिचालक उदयलाल पिता हरजीलाल खारोल थे जो रास्ते मे त्रिदेव महादेव कंवलियास दर्षन करने गाडी रोड के किनारे खडी कर चले गये। वापस आये तब गाडी मे रखे बेग सहित जिसमे 1,45,810/-रूपये नही मिले। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

आरोपी पप्पूसिंह राजपूत को डिटेन कर पुछताछ की गई तो उसने अपने साथी भैरूलाल मेघवंशी को नकद पैसे के बारे मे जानकारी देना तथा भैरूलाल द्वारा मोटरसाईकिल पर आकर पिकअप की केबिन खोलकर ले जाना स्वीकार किया। दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर पुछताछ की गई तथा मामले में माल नकद राशि 1,45,810/-रूपये आरोपी के कब्जे से बरामद किये गये।

आमलीगढ़ पंचायत में नालियों की सफाई के नाम पर लीपापोती का आरोप

स्मार्ट हलचल | मंगरोप

हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र की आमलीगढ़ पंचायत में नालियों की सफाई को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है।ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में पंचायत प्रशासन द्वारा नालियों की सफाई करवाई गई,लेकिन यह कार्य केवल औपचारिकता तक ही सीमित रहा।ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के कई मोहल्लों में नालियों की आंशिक सफाई तो कर दी गई,लेकिन नालियों के ऊपर और आसपास उगी झाड़ियों व कचरे को हटाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।इसके चलते नालियों में दोबारा गंदगी भरने और जल निकासी बाधित होने की आशंका बनी हुई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नालियों की पूर्ण सफाई के साथ-साथ आसपास की झाड़ियों को नहीं हटाया गया,तो बरसात के मौसम में जलभराव और गंदगी की समस्या गंभीर हो सकती है।ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से मांग की है कि नालियों की समुचित व स्थायी सफाई करवाई जाए,ताकि आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े।ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के साथ आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

विशेष निरोधात्मक अभियान : प्रदेश में 2 लाख 34 हजार लीटर से अधिक वॉश नष्ट

स्मार्ट हलचल | उदयपुर

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए जनवरी माह में 2 लाख 34 हजार 371 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाही में 894 केस दर्ज करते हुए 718 को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई। प्रदेश में जनवरी माह में 2 लाख 34 हजार 371 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में भारत निर्मित विदेशी मदिरा 622, देशी मदिरा 4921, अवैध मदिरा 5468, बीयर 1052 बोतल सहित एक किलोग्राम भांग को सीज किया गया।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रषासन अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जनवरी माह में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्तता पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 894 केस दर्ज करते हुए 718 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

मंगरोप महात्मा गांधी स्कूल में मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम, 82 बालिकाओं के चेहरे खिले

स्मार्ट हलचल | मंगरोप

कस्बे में स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में बुधवार को मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम के तहत विद्यालय की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 8 2 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गईं, जिनमें से 45 बालिकाएं कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास की हैं। साइकिल प्राप्त कर बालिकाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।साइकिल पाकर छात्राओं ने विद्यालय परिसर में साइकिल चलाकर खुशी जाहिर की,जिससे उनके चेहरे खिल उठे।कार्यक्रम में एसडीएमसी सदस्य बलवंत सिंह पुरावत,शांतिलाल किर,भैरूलाल सोमानी,राघव सोमानी,प्रकाशचंद्र मारू,भगवानलाल गुर्जर,गोविंद वैष्णव,बादल जाट,एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार खटीक,गोपाल किर,राहुल सालवी सहित अभिभावक नगजीराम माली व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम का मंच संचालन स्थानीय अध्यापक रामनारायण माली ने किया।इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यालय व छात्रावास के विकास हेतु महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में बिजली के 3 फेज कनेक्शन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। साथ ही जानकारी दी गई कि एक वर्ष पूर्व लॉन्ड्री मशीन मंगवाई जा चुकी है।लेकिन कनेक्शन नहीं मिलने से वह बेकार पड़ी है।विद्यालय के लिए 100 टेबल व स्टूल देने की घोषणा बलवंत सिंह पुरावत,राघव सोमानी,भैरूलाल सोमानी,संपत सुथार व जीतू सिंह राणावत द्वारा की गई।

स्कूल के कमरों की रंग-रोगन व्यवस्था के लिए भामाशाहों भैरूलाल सोमानी 11 हजार,बलवंत सिंह पुरावत 11 हजार व राघव सोमानी एवं भगवानलाल गुर्जर दोनों ने 11 हजार की संयुक्त राशि देने की घोषणा की।इसके साथ ही भगवत सिंह पुरावत ने विद्यालय परिसर में सरस्वती प्रतिमा सहित मंदिर निर्माण की घोषणा की।सभी अतिथियों ने एक स्वर में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया।कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बालिकाओं को उच्च शिक्षा तथा स्कूली खेल स्पर्धाओं में भाग लेकर गांव का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।विद्यालय में सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।प्रधानाचार्या वंदना कौशिक के नेतृत्व में अध्यापक जाकिर हुसैन सहित समस्त विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का ओपर्णा ओढ़ाकर स्वागत किया।साइकिल प्राप्त करने वाली प्रमुख बालिकाओं में तनीषा खटीक,ज्योति जटिया,जोया बानू,नेहा योगी,काली राव,इशिका बैरवा,कोमल शर्मा,करीना सांसी,सपना नायक सहित कुल 82 छात्राएं शामिल रहीं।आयोजित कार्यक्रम ने बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी नई उड़ान दी।

यातायात नियमों को लेकर आमजन को किया जागरूक

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालना हेतु उन्नत इलेक्ट्रोनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालना हेतु उन्नत इलेक्ट्रोनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली स्थापित की जा रही है। जिससे प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए गए उल्लघनों के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ई-चालान स्वतः जारी कर वाहन स्वामियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजे जाएगें। 11.02.2026 को यातायात पुलिस, भीलवाड़ा द्वारा वाहन चालाको को ओवरस्पीड़ (निर्धारित गति सीमा से अधिक गति)से वाहन नही चलाने, हेलमेट के बिना वाहन नही चलाना, दो-पहिया वाहन पर तीन सवारी नही बिठाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग नही करने, सीटबेल्ट के बिना वाहन नही चलाने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 लेन सिस्टम की पालना करने एवं गलत दिशा में वाहन नही चलाने हेतु जागरूक किया गया।

जानलेवा हमले में घायल जगदीश की उदयपुर में मौत, परिजनों ओर समाजजनों ने मोर्चरी पर दिया धरना, आरोपितों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा (मांडल)। मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में एक फरवरी को हुई हिंसक घटना में गंभीर रूप से घायल जगदीश सिंह दरोगा का उदयपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार रात निधन हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार सुबह से परिजन व समाजजन जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और शेष आरोपितों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार, जगदीश के बेटे पर एक युवती को चार-पांच दिन पूर्व भगा ले जाने का आरोप था। इसी मामले को लेकर एक फरवरी की शाम चारभुजानाथ मंदिर में बैठक बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि जगदीश ने स्वयं को नशे की हालत में बताते हुए बैठक में आने से इनकार कर दिया, लेकिन बैठक में जो निर्णय होगा उसे स्वीकार करने की बात कही थी। मंदिर में उपस्थित कुछ लोग जगदीश के नहीं पहुंचने से नाराज होकर भीड़ के रूप में उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि घर में तोड़फोड़ की गई, उनकी मां व पत्नी को बाहर निकाला गया तथा परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। जगदीश को कमरे से बाहर घसीटकर गंभीर रूप से पीटा गया और मंदिर की ओर ले जाया गया। इस दौरान घर में आगजनी की घटना भी हुई। हमले में जगदीश के अलावा गीता देवी, लाड़ी देवी, महावीर, सीमा और 13 माह की बच्ची ज्योति घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि गंभीर हालत में जगदीश को उदयपुर रैफर किया गया, जहां मंगलवार रात उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक का शव बुधवार सुबह भीलवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। बुधवार सुबह से समाजजन बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मांडल पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण आरोपितों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा।

धरने की सूचना पर मांडल डिप्टी राहुल जोशी और थानाधिकारी रोहिताश यादव मौके पर पहुंचे तथा लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

वहीं मांडल थाना प्रभारी रोहिताश यादव ने बताया कि मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से इनकार किया। देर रात तक मोर्चरी पर धरना जारी रहा और पोस्टमार्टम नहीं हो सका। समाजजनों ने गुरुवार को पुनः मोर्चरी पर धरना जारी रखने की बात कही है। स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महुआ में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित

साइकिल पाकर छात्राओं के खिले चेहरे

स्मार्ट हलचल

महुआ। महुआ क्षेत्र के महात्मा गांधी विद्यालय महुआ में साइकिल वितरण कार्यक्रम किया गया जिसमे मुख्य अतिथि भाजपा महुआ मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा विशिष्ट अतिथि मंडल उपाध्यक्ष रणवीर सिंह शक्तावत विद्यालय स्कूल के डीडीओ अधिकारी व उप प्राचार्य नटवर खटीक ने कहा कि साईकिल वितरण का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं आवागमन को सुदृढ़ बनाना है विद्यालय प्रतिनिधि श्याम लाल माली मंडल महामंत्री बनवारी लाल धाकड़ वार्ड पंच कमलेश जैन समाजसेवी शिवकुमार वर्मा मंडल अध्यक्ष बृजमोहन शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है जिसमें विकास की कोई कमी नहीं है और अभी हाल ही में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के अनुशंसा पर विधानसभा की अनेक स्कूलों में कमरों शौचालयों टिनसेट बनाने को लेकर करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य अनीता रजवानिया दिनेश कंवर कनिष्ठ लिपिक प्रभु लाल धाकड़ अध्यापक भरत सेन अर्जुन नागर सहित छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

आज से शुरू होंगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल

स्मार्ट हलचल

मेड़ता रोड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ होने जा रही हैं। प्रदेशभर में इन परीक्षाओं को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष लगभग 20 लाख परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, जिससे शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहे हैं।

परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक कक्ष में रोल नंबर के अनुसार सीटें अंकित कर दी गई हैं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा एवं प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

इसी क्रम में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जारोड़ा कलां में भी परीक्षा संबंधी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहां कुल 321 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। विद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्र को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। विद्यालय के पीईईओ मोहम्मद अख्तर नदीम ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के बैठने के स्थानों पर रोल नंबर अंकित कर दिए गए हैं और परीक्षा केंद्र पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शिक्षा विभाग ने भी सभी केंद्राधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न हो। परीक्षार्थियों से भी समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

गिलूंड में शितलेश्वर महादेव एव शीतला माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न

स्मार्ट हलचल | ओम जैन

शंभूपुरा।चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव गिलूंड में 3 दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन 9 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया।

गिलूंड के पूर्व सरपंच हेमराज भोई ने जानकारी देते हुए बताया कि गिलूंड में महलों के पास शीतला माता मंदिर में शितलेश्वर महादेव एव शीतला माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत समस्त ग्रामवासियों द्वारा आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन में प्रथम दिन 9 फरवरी सोमवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमे बड़ी संख्या में गांव की माताए अपने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा में शामिल हुई, कलश यात्रा के दौरान पहुंचे विधायक चंद्रभान सिह आक्या ने पुष्पवर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया।

मंगलवार को प्रातः हवन यज्ञ एव धार्मिक कार्यक्रम हुए। वही 11 फरवरी बुधवार को सुबह शुभमुहूर्त 10:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसके पश्चयात पूर्णाहुति दी गई। जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया।

तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन में सर्व समाज के ग्रामवासी मौजूद रहे, ओर हर्षोल्लास के साथ यह महोत्सव सभी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर प्रशिक्षण का हो रहा आयोजन

विद्यार्थियों का हो सर्वांगीण विकास - दाधीच

स्मार्ट हलचल

रायपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुरा के निर्देशानुसार रायपुर ब्लॉक के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए चार दिवसीय स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

आरपी कान्हा राम ने बताया कि स्कूल हेल्थ एण्ड वैलनेस एम्बेसडर चार दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण 2025-26 सन्दर्भ कक्ष राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय घाटी रायपुर में आयिजित किया जा रहा है।शिविर निरीक्षण के दौरान सीबीईओ रायपुर नरोत्तम कुमार दाधीच ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण की महत्वता पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया । शिविर प्रभारी सत्यनारायण तातेला ने शिविर का संक्षिप्त परिचय दिया । प्रशिक्षक नवीन कुमार बाबेल ने स्वस्थ बढ़ना ,भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता, जेंडर समानता मॉड्यूल को गतिविधियों के माध्यम से समझाया। साथ ही एस एच डबल्यू पी ऐप के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षक पूनम जीनगर ने स्वास्थ्यपरक आदतों, पारस्परिक संबंध के बारे में बताया।

खेत तक रास्ता नहीं, गांगलास पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कलेक्टर पहुंचे, समाधान के दिए सख्त निर्देश

स्मार्ट हलचल | भीलवाड़ा

जिले की गांगलास ग्राम पंचायत में किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए समुचित मार्ग नहीं मिलने की समस्या को लेकर सोमवार को प्रशासन सक्रिय नजर आया। गांव निवासी रामनाथ, शंकरलाल एवं प्रभुलाल लोहार सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से रास्ते की मांग उठाई जा रही थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम, विकास अधिकारी (बीडीओ), पटवारी एवं ग्राम सरपंच सहित राजस्व व पंचायत विभाग का अमला मौजूद रहा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह उप जिला कलेक्टर परमजीत के पहुंचते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और अपनी समस्याएं खुलकर रखीं। ग्रामीणों ने बताया कि खेत तक जाने के लिए नियमित रास्ता नहीं होने से खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फसल की ढुलाई, ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों के आवागमन में भारी दिक्कत आती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि मामले में किसी प्रकार का आपसी विवाद नहीं है, बल्कि वर्षों से खेत तक पहुंचने के लिए वैधानिक मार्ग का अभाव है। कलेक्टर ने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ली तथा मौके पर सीमांकन व आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को उनके खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा समाधान की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। दौरे के बाद ग्रामीणों में सकारात्मक माहौल देखा गया और लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की उम्मीद जगी।

आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत बन का खेड़ा में बैठक आयोजित

स्मार्ट हलचल

सवाईपुर। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की प्रथम मासिक बैठक मंगलवार को बनकाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वी सी रूम मे आयोजित की गयी । जिसमे आयुष्मान आरोग्य मन्दिर राजकीय आयुर्वेद औषधालय के प्रभारी डॉ. मुकेश वैष्णव ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा 2025-26 के तहत, भीलवाड़ा जिले की बन का खेड़ा ग्राम पंचायत को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की पायलट परियोजना के लिए चुना गया है । इस पहल के माध्यम से, चयनित गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा जो स्वस्थ, तंबाकू मुक्त और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे । आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से, चयनित गांव में प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति (वात, पित्त, कफ) का परीक्षण किया जाएगा, और बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्वानुमानित उपचार, दवा और आहार संबंधी परामर्श प्रदान किए जाएंगे । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी खर्च को कम करना, स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और आयुर्वेद सहित पारंपरिक स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों की सार्वजनिक स्वीकार्यता को मजबूत करना है । इस योजना के तहत, निर्धारित 18 स्वास्थ्य संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल करने पर ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी । प्रमुख घटकों में प्रकृति परीक्षण, एनीमिया परीक्षण, रक्तचाप और शर्करा की जांच, तंबाकू मुक्त वातावरण, टीबी और खसरा-रूबेला उन्मूलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्ण टीकाकरण, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रोफाइल का रखरखाव और मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग आदि शामिल हैं । इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, ग्राम स्तर पर आरोग्य मित्र और आरोग्य सखियों का चयन और प्रशिक्षण किया जाएगा । प्रत्येक वार्ड और बस्ती में स्वास्थ्य जागरूकता, घरेलू उपचार, औषधीय पौधों के उपयोग, योग-व्यायाम, पोषण और नशामुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे । इस योजना के संचालन के लिए आयुर्वेद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना एवं जन संपर्क, वन विभाग और यूनिसेफ के साथ समन्वय करेंगे । उपरोक्त बैठक मे प्रधानाचार्य बरदा लाल रेगर, चिकित्साधिकारी सीएचसी सवाईपुर के डॉ. राहिल बेग मिर्जा, सीएचऔ देवेंद्र सिंह राणावत, नर्स लाड कुमारी आचार्य, एएनएम आशा धोबी, कृषि अधिकारी भूरी मीणा, आशाएं जुबेदा, सीमा, ज्ञाना, सीता, विमला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता, अनीशा,माया, सरोज, सुमित्रा, चंचल, अध्यापक रामेश्वर लाल कुमावत और उमेश कुमार खटीक, नेहरू युवा मंच के सदस्य समाज सेवी शंकर लाल जाट उपस्थित रहे।

कनेछन कलां में किशोरी शैक्षणिक बाल मेला आयोजित

35 स्टालों पर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

स्मार्ट हलचल | शाहपुरा

कनेछन कलां स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बुधवार को किशोरी शैक्षणिक बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण कुमावत ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बृजमोहन महावर, पीईईओ रज्जब अली, सरजीत कुमार, नंदकिशोर शर्मा, जीताराम बैरवा, सूर्यप्रकाश शर्मा, नीटू कुमार, प्रहलाद मीणा, पवन कुमार जीनगर सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। बाल मेले में स्थानीय छात्राओं द्वारा शिक्षण विषयों से संबंधित लगभग 35 स्टालों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मेले में 15 विद्यालयों की लगभग 300 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

आवासीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संतरा कुमारी ने बताया कि छात्राओं ने एटीएम मशीन, ईवीएम मशीन, चंद्रयान-3, 'आओ देखो जानो' तथा 'मैं हूं कौन' जैसे शैक्षणिक मॉडल और गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में रेखा शर्मा, नूतन आमेटा, शीला जाट, प्रियंका राठौर, रेनू गोचर, श्रीदेवी टेलर, मिट्ठूलाल धोबी, ओमप्रकाश खारोल, भामाशाह आशीष त्रिपाठी, प्रियंका शर्मा, प्रहलाद मीणा, संतोष आलोरिया, राजकुमारी सेन, महावीर रेगर, मुकेश जाट, भूपेंद्र सिंह, बृजेन्द्र सैनी, महेंद्र सिंह शेखावत, पूजा शर्मा, रिंकू कुमावत सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन अध्यापक सूर्य प्रकाश शर्मा ने किया।

हिन्दुस्तान जिंक द्वारा आगुचा में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग का किया शुभारंभ

युवाओं के मजबूत भविष्य निर्माण हेतु अनूठी पहल, विद्यार्थियों ने दिखाया बढ़ चढ़कर रुझान

स्मार्ट हलचल

भीलवाड़ा। हिन्दुस्तान जिंक रामपुरा आगुचा माइंस द्वारा आगुचा क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से युवाओं को को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अनूठी पहल में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर रुझान दिखाया। योजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी गुलाबपुरा दिव्यराज सिंह चुंडावत एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिन्दुस्तान ज़िंक आगुचा क्लस्टर के यूनिट हेड वेकेश चित्तौड़ा, हुरडा के एसीबीईओ के. पी. सिंह ने किया । इस अवसर पर रामपुरा आगुचा माइन के एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटर्नल लाइजनिंग हेड अभिमन्यु सिंह राणावत, हेड सीएसआर भुवनेश शर्मा, जिंक कौशल केंद्र की इंचार्ज सुलेखा जैन और अनुष्का ग्रुप के सेक्रेटरी राजीव सुराणा भी मौजूद थे। अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को बैग, मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका अनुष्का टाइम्स का विरतरण किया गया। दिव्यराज सिंह चुंडावत ने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में लगन और कड़ी मेहनत की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। अपने बचपन के रिसोर्स की कमी वाले एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे लगातार कोशिश और मजबूत इरादा लोगों को चुनौतियों का सामना करने और सफलता पाने में मदद कर सकता है। वेकेश चित्तौड़ा ने विद्यार्थियों को अपनी अंदर की ताकत और फोकस का अच्छे से उपयोग करने के लिए मोटिवेट किया, और कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए सेल्फ-डिसिप्लिन और पक्का इरादा जरूरी है। भुवनेश शर्मा ने स्टूडेंट्स को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और कार्यक्रम को सफलता पूर्वक इम्प्लीमेंट करने के लिए अनुष्का ग्रुप की सराहना की। अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अनुष्का ग्रुप के निदेशक राजीव सुराणा ने कहा कि 100 दिनों तक संचालित यह योजना रामपुरा आगुचा क्षेत्र के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर हैं और सभी विद्यार्थियो को यह विश्वास जताया कि अग्रिम कक्षाओं को भी इससे अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ चलाया जाएगा। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक रामपुरा आगुचा परिधि क्षेत्र से 150 से अधिक युवा विद्यार्थी उपस्थित थे।

41 छात्राओं को बांटी निःशुल्क साइकिलें

स्मार्ट हलचल

लाडपुरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को साइकिल वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। शक्ति केंद्र संयोजक मोहन सिंह शक्तावत ने बताया कि योजना के तहत समारोह में कक्षा 9 वी की 41 छात्राओं को अतिथियों द्वारा साइकिल वितरित की गई। साइकिलें पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें निशुल्क साइकिलें दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रशासक प्रकाश कंवर शक्तावत थी। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी। भामाशाह महिपाल सिंह शक्तावत ने बताया कि साइकिल पाकर छात्राएं अत्यंत प्रसन्न हुई। संस्था प्रधान ने सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।

केकड़ी सिटी थाने में बदलाव की गूंजः 'लेडी सिंघम' कुसुमलता मीणा लाइन हाजिर, शहर में भावनाओं का उफान

स्मार्ट हलचल

केकड़ी। केकड़ी सिटी थाने में हुए ताज़ा प्रशासनिक फेरबदल ने शहर के माहौल को एकाएक भावुक, चर्चित और संवेदनशील बना दिया है। अपनी निष्पक्ष, निर्भीक और अनुशासित कार्यशैली से आमजन के बीच 'लेडी सिंघम' के रूप में विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाली सिटी थानाधिकारी इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके स्थान पर अनिल शर्मा को सिटी थानाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इस निर्णय के बाद शहरभर में चर्चाओं का दौर तेज है, वहीं सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की मानो बाढ़ सी आ गई है, लोग एसपी के आदेश को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे है। 22 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालने वाली इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा ने लगभग एक वर्ष तीन माह के अपने कार्यकाल में सख्त पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का ऐसा संतुलन प्रस्तुत किया, जिसने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली को नई ऊर्जा प्रदान की। 80 से महिला व बच्चियों को दस्तयाब कर सुरक्षित परिजनों तक पहुँचाने की कार्रवाई ने न केवल उनकी संवेदनशीलता और सजगता को रेखांकित किया, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी सुदृढ़ किया। कॉलेज और स्कूलों में पहुँचकर छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित करना, उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और अपना स्वयं का संपर्क नंबर उपलब्ध कराते हुए किसी भी परिस्थिति में बेझिझक संवाद का संदेश दिया।

एक साल में गिरा आपराधिक थाने का आपराधिक ग्राफ, बड़ी वारदातों का हुआ खुलासा

अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर भी इंस्पेक्टर मीणा का कार्यकाल उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा रहा। महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करते हुए 5 नथ लूट की वारदातों का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे शहर में राहत और संतोष की अनुभूति हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई प्रभावी कार्यवाहियों ने अवैध गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार किया। वाहन चोरी जैसे आमजन को प्रभावित करने वाले अपराधों पर भी उनकी सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। डंपर, ट्रैक्टर, बाइक सहित कई वाहनों की चोरी के मामलों में तुरंत कार्रवाई कर न केवल रिकवरी सुनिश्चित की गई, बल्कि वाहन चोरों के गिरोहों का पर्दाफाश कर अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटियों की धरपकड़, दर्ज प्रकरणों की समयबद्ध जांच और कोर्ट में चालान पेश करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान की।

आमजन से सीधा संवाद और सहज उपलब्धता से बनी पहचान-

इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा की कार्यशैली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता रही–आमजन से सीधा संवाद और सहज उपलब्धता। थाने की चौखट आम नागरिकों के लिए भरोसे का दरवाज़ा बनी रही, जहाँ हर व्यक्ति अपनी समस्या बिना झिझक रख सकता था। इंस्पेक्टर कुसुमलता मीणा ने केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रही, बल्कि थाने की आंतरिक व्यवस्था और पुलिस कर्मियों के कल्याण पर भी समान रूप से केंद्रित रही। थाने परिसर में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना, फैली अव्यवस्था को सुधारना, मैस का नए सिरे से निर्माण करवाना और पुलिस कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें बेहतर कार्यपरिस्थिति उपलब्ध कराई। साथ ही थाने में आने वाले पीड़ितों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था कर उन्होंने पुलिसिंग के मानवीय पक्ष को सशक्त किया।

जाते-जाते भी मानवीय मूल्यों की मिसाल-

लाइन हाजिर किए जाने के पश्चात विदाई के क्षणों में भी इंस्पेक्टर मीणा ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक जरूरतमंद गरीब महिला को निजी व्यय से 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके कच्चे घर की दीवार गिरने से वह विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही थी। सहायता पाकर महिला और उसके विकलांग पति की आँखों में झलकते आभार और भावनाओं ने उस क्षण को अत्यंत मार्मिक बना दिया।

शौच के लिए निकली नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज

स्मार्ट हलचल | खखरेरू/फतेहपुर

थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री 9 फरवरी की शाम लगभग 5:30 बजे घर पर सौंच क्रिया के लिए जंगल की ओर जाने की बात कहकर निकली थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब किशोरी वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका।

परिजनों द्वारा आसपास के गांवों, रिश्तेदारों एवं परिचितों के यहां भी जानकारी की गई, लेकिन किशोरी के बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराते हुए लिखित तहरीर दी। इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर किशोरी की गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा सभी संभावित बिंदुओं पर जांच की जा रही है और किशोरी की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हिंदुस्तान जिंक की समाधान परियोजना के तहत् रैली का आयोजन

स्मार्ट हलचल

चित्तौड़गढ़। हिन्दुस्तान जिंक के सीएसआर के तहत बायफ के सहयोग से संचालित समाधान परियोजना के तहत चंदेरिया क्षेत्र के 48 गांवों में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम वजीरगंज एवं गणेशपुरा में वत्स रैली का आयोजन किया गया।

उन्नत नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन पर जोर देते हुए इस रैली में चंदेरिया के कंथारिया सेंटर के तहत कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए 21 उन्नत नस्ल के बछड़े-बछड़ियों को प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस सेंटर पर कुल 1000 कृत्रिम गर्भाधान किए गए, जिनसे 455 बछड़े पैदा हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 80 प्रगतिशील पशुपालकों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. जयदेव सिंह ने पशुपालकों को विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, पशु मंगला एवं सॉर्टेड सीमन नस्ल सुधार के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पशुधन निरीक्षक शीला भाट ने पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव और शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर के महत्व को समझाया। गणेशपुरा में 22 बछडे वत्स रैली में आये एवं 40 किसानो ने भाग लिया। अतिथि पशुपालन विभाग से डॉ. सुमेर सिंह सहायक सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चितोड़गढ़, डॉ. मुकेश सक्सेना पशु चिकित्सक, डॉ. रूचि शर्मा पशु चिकित्सक, बायफ उदयपुर से डॉ. दिनेश प्रसाद रतुरी, डॉ. अनुज डिक्सित उपस्थित थे डॉ. मुकेश सक्सेना ने पशुपालन की सम्पूर्ण योजना, सॉर्टेड गर्भाधान आदि की जानकारी दी, डॉ. रूचि शर्मा ने पशुओ में होने वाली मोसमी बीमारी व मिनरल मिक्सचर के बारे में जानकारी प्रदान की।

वत्स रैली में पशुपालन विभाग से आई टीम ने बछडीयो का अवलोकन किया जिसमे से डगला खेड़ा से किसान कन्हया लाल भंडारी की गिर नस्ल की बच्छडी को प्रथम पुरुस्कार व सुरेश मीणा गणेशपुरा ने दुसरे स्थान प्राप्त किया। किसानो को दी जानकारी में से प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया जिसमें विजेताओं को मिनरल मिक्सचर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सबसे स्वस्थ और अच्छी नस्ल के अन्य बछड़ों के पशुपालको को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। समाधान परियोजना के माध्यम से चंदेरिया क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान, सॉर्टेड सीमन, बकरी पालन, पशु स्वास्थ्य शिविर, डीवर्मिंग एवं हरित धरा जैसे हरा चारा विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर चंदेरिया स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स की सीएसआर एवं बायफ की टीम उपस्थत थी।

बकाया जल बिल न भरने वालों पर गिरेगी गाज

विभाग ने दी कनेक्शन काटने व कानूनी कार्यवाही की चेतावनी

स्मार्ट हलचल | उदयपुर

शहर में जल बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने उदयपुर शहर के नगर खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के उन उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिनका जल राजस्व लंबे समय से बकाया है। अधिशाषी अभियन्ता विमल प्रकाश सिसौदिया द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों के सभी बकायादारों को 7 कार्यदिवसों के भीतर अपनी बकाया राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया जल राजस्व जमा नहीं कराने पर केवल कनेक्शन ही नहीं कटेगा, बल्कि जन माँग वसूली अधिनियम और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 229 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत विभाग बकायादारों के खिलाफ वारंट जारी करने, संपत्ति कुर्क करने और उसकी नीलामी जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर के हस्ताक्षर अभियान की आज हुई शुरुआत

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर के नेतृत्व में नगर परिषद ब्यावर द्वारा कचरा संग्रहण पर लगाए गए वसूली के खिलाफ़ हस्ताक्षर अभियान...

ब्यावर नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण को लेकर लगाए गए शुल्क के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर ने वार्ड नंबर 18 के निवर्तमान पार्षद भारत बाघमार ने गजानंद जी का मंदिर चमन चौराया से आये हुए कांग्रेस के नेताओं का दुप्पटा पहनाकर स्वागत किया एवं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जिसमें घर घर पहुंचकर हस्ताक्षर करवाए वार्ड ओर शहर की जनता में इस कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली अभियान में पूर्व विधायक माणक डाणी ने आमजन से अपील करते हुए बताया कि नगर परिषद द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करना ब्यावर की जनता के साथ धोखा है , राजेंद्र ओस्तवाल ने कहा कि नगर परिषद द्वारा वसूली करना हठधर्मिता को दर्शाता है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर के अशोक रांका ने कहां कि नगरपरिषद द्वारा करोड़ो में ठेकेदार को टेंडर देकर नगर परिषद कि आय को कम ।करके नगर परिषद को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आम जनता से करना चाहती है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं अभियान में राष्ट्रीय सेवादल कांग्रेस सचिव कल्पना भटनागर, प्रदेश सचिव सोहन मेवाड़ा, जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष डॉ अरविंद माथुर, नि0पार्षद भारत बाघमार, राजेन्द्र तुनगरिया, रामनिवास सेन, राजेश शर्मा, अजय स्वामी, घनश्याम फुलवारी, चिराग शर्मा, 'र्क्स जिलाध्यक्ष राम यादव, युवक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष सांखला, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, विजेंद्र प्रजापत, नारायण मेहड़ा, बाबूलाल पंवार, धर्मेंद्र बारिया, सोमदेव साहू, अशोक पंडित, चेतन भट्ट, रामस्वरूप डागर, सुरेश साहू, संदीप सांखला, वृत्तंज्य आर्य, घनश्याम बारोलिया, रामा माहेश्वरी, कान्हा पंवार, हरीश बुनकर आदि ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के विरोध में भाग लिया।

बजट 2026-27 में – जिला प्रशासन के प्रयासों से अमृतकौर चिकित्सालय के लिए 15 करोड़ स्वीकृत

स्मार्ट हलचल

ब्यावर। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए जिला कलेक्टर कमल राम मीना द्वारा भेजे गए 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति जिला प्रशासन के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिससे राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने गत दिनों राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था, जिसमें अस्पताल के हॉल एवं कमरों की स्थिति जर्जर पाई गई। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अस्पताल में तीन नए हॉल/कमरों की आवश्यकता बताई गई, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध कक्षों की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने बताया कि राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय का भवन लगभग 70 वर्ष पुराना है तथा अस्पताल के तीन हॉल एवं बरामदे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे चिकित्सकों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अस्पताल के तीन कमरे एवं हॉल मय बरामदा असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं।

चिकित्सालय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुराने एवं क्षतिग्रस्त हॉल व कमरों के स्थान पर नवीन हॉल मय बरामदा निर्माण, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत, टाइल्स कार्य, सड़क, नाली एवं सीवरेज व्यवस्था तथा जल निकासी सुधार के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

इस बजट स्वीकृति से चिकित्सालय में चिकित्सकों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा तथा मरीजों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। साथ ही इस अस्पताल से ब्यावर जिले सहित राजसमंद, पाली एवं भीलवाड़ा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण बजट प्रावधान से चिकित्सा विभाग एवं आमजन में प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार की सकारात्मक पहल को बल मिलेगा।

युवाओं, महिलाओं, किसानों को बजट में किया फोकस-चौधरी

पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी ने किया गांवों का दौरा

स्मार्ट हलचल | हरसौर

बुधवार को कस्बे सहित आसपास के गांवों के एकदिवसीय दौरे पर आए पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी ने आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। भाजपा नेता हुकमाराम बाजियां की अगुवाई में कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने चौधरी का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में युवाओं, महिलाओं एवं किसानों पर फोकस किया गया है। बुनियादी ढांचे, उद्योग, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को लेकर मजबूत प्रावधान किए गए हैं। 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 4 लाख नौकरियों के रोडमैप और 'राज सुरक्षा' जैसी क्रांतिकारी योजनाओं से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। 42,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का संकल्प लिया गया है, जो राजस्थान की रफ्तार को नई दिशा देगा। उन्होंने संगठन की गतिविधियों एवं राज्य सरकार के कार्यों का फीडबैक लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विचारधारा पर कार्य करने वाली पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं से भी चौधरी को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य नानूराम मेघवाल, महीराम बिश्नोई, मनमोहन सेन, अंकित सियाक, नानूराम दादरवाल, ओमप्रकाश चोयल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

करोड़पति की कार से एक्सीडेंट मामले में रिपोर्ट कर्ता ने किया समझौता, बेटे की जगह चालक पेश

स्मार्ट हलचल

कानपुर। यहां के बहुचर्चित करोड़पति तम्बाकू व्यवसाई के के मिश्रा के बेटे शिवम द्वारा किए गये लेम्बोर्गिनी कार से चार लोगों को टक्कर मारने के मामले में एकदम से नया मोड़ आ गया है। ऐसा मुकदमा जारी करने वाले वादी द्वारा समझौता कर लेने और बेटे शिवम की जगह चालक मोहन द्वारा कार चलाने की बात कहने और इस आधार पर कोर्ट में अर्जी डालने की वजह से हुआ है।

मिली जानकारी के मुताबिक पहले कथित ड्राइवर ने दोपहर में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिर मुकदमा दर्ज कराने वाले मो. तौसीफ ने समझौता कर लिया।

यह बात अलग है कि कोर्ट ने आरोपी नहीं मानते हुए ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं नाम नहीं है। इसलिए उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई। कार अभी थाने में ही रहेगी।

इसी मामले में इससे पहले ड्राइवर मोहन वकील नरेंद्र कुमार यादव के साथ कोर्ट पहुंचा। मोहन ने कहा कि शिवम मिश्रा की गाड़ी मैं ही चला रहा था। शिवम को दौरा पड़ गया था। इस बीच उसने आगे जो बयान दिया उसके मुताबिक उसका कहना है कि उस वक्त मैं घबरा गया था। कुछ समझ नहीं आया। उसी वक्त हादसा हो गया। जब शीशा तोड़ा और दरवाजा खोला गया तो मैं नीचे से निकल गया था। बाउंसर ने शिवम को निकाला था। हादसे के बाद मैं कोने में खड़ा हो गया था। शिवम को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया था। फिलहाल पुलिस अपनी जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई पर लगातार जुटी हुई है। पुलिस की जांच के जाड़े मेंकर चालक के रूप में अभी तक शिवम ही आरोपी साबित हुआ है। जिसके आधार परकार्रवाई की जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन

स्मार्ट हलचल | खखरेरू/फतेहपुर

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने क्षेत्र में व्याप्त गंभीर समस्याओं को लेकर ग्राम सभा पौली के पास सड़क किनारे धरना-प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया।

धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रमुख रूप से निम्न समस्याएं उठाई

आवारा गोवंशों का आतंकजंगली जानवरों व बंदरों का बढ़ता खतरा,रोजाना अघोषित विद्युत कटौती,बंद पड़ी सहकारी समितियों को चालू न किया जाना,खाद की भारी किल्लत,सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होना किसानों ने बताया कि खाद और बिजली की कमी के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है। किसी तरह फसल तैयार भी हो जाती है तो आवारा गोवंश, वन्य जीव और बंदरों के आतंक से फसलें चौपट हो रही हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि गांवों में लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। कई किसान बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं।

धरने के दौरान किसान नेता तहसील स्तर के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर एक्सईएन महावीर सिंह,एसडीओ किशनपुर,जेई रसूलपुर सानी,कनपुरवा पावर हाउस के अधिकारी पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने अघोषित विद्युत कटौती की समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

वहीं जंगली जानवरों व बंदरों के आतंक के मुद्दे पर वन विभाग के रेंजर ने स्पष्ट कार्यवाही से पल्ला झाड़ लिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए। बाद में रेंजर द्वारा वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देकर मौके से चले जाने पर किसानों में नाराजगी और बढ़ गई।

धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित किसान नेता

अखिलेश सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)जितेंद्र त्रिपाठी (जिला महासचिव)राम भजन सिंह (तहसील संरक्षक)रामशरण सिंह (तहसील महासचिव खागा)करण सिंह पटेल (धाता ब्लॉक अध्यक्ष) सत्यजीत सिंह, दिलीप सिंह, राधेश्याम सिंह, सत्येंद्र सिंह, हेमंत सिंह, जय सिंह, सुशील दुबे,सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

नारायणपुर में सिविल न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, न्यायिक कार्यों का बहिष्कार

स्मार्ट हलचल

नारायणपुर। कस्बे में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय स्तर पर राहत की मांग को लेकर बुधवार को अभिभाषक संघ, डीडराइटर्स और स्टाम्प वेंडरों ने तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारायणपुर उपखंड स्तर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग उठाते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। एडवोकेट रविंद्र शर्मा ने कहा कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्राधिकार को अलवर जिले के थानागाजी से हटाकर कोटपुतली-बहरोड़ जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बदलाव के कारण स्थानीय पक्षकारों और आमजन को कानूनी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ समय की भी काफी बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि सुलभ और त्वरित न्याय सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय स्तर पर न्यायालय नहीं होने से लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इसके चलते तहसील कार्यालय में होने वाले रजिस्ट्री, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज संबंधी कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, जिससे दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।

धरने के दौरान एडवोकेट विजय कुमार महर्षि, रामपाल सैनी, दिनेश शर्मा, रामकृष्ण चौपड़ा, लक्ष्मण प्रसाद दर्जी, कैलाश चंद, तरुण तिवाड़ी, रणजीत यादव, अर्जुन लाल, राजेन्द्र प्रसाद, श्योराम, सचिन गुर्जर, नरेंद्र शर्मा और दाताराम सैनी सहित बड़ी संख्या में संघ के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सदन ठप, सवाल अनुत्तरित लोकतंतकी कसौटी पर कांग्रेस का रवैया

कांतिलाल मांडोत

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है।

संसद का बजट सत्र देश की आर्थिक दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, लेकिन जब यही मंच हंगामे, नारेबाजी और रणनीतिक अवरोध का अखाड़ा बन जाए, तो सवाल सिर्फ कार्यवाही के ठप होने का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के क्षरण का भी उठता है। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, प्रश्नकाल का बार-बार स्थगन और विपक्ष का निरंतर विरोध, इसी चिंता को गहरा करता है। इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है।

लोकसभा में विपक्ष का अधिकार बहस करना, सवाल उठाना और सरकार को जवाबदेह ठहराना है। यह अधिकार संविधान और संसदीय परंपराओं से सुरक्षित है। लेकिन जब यह अधिकार सदन को चलने ही न देने की जिद में बदल जाए, तो वह लोकतंत्र की मजबूती के बजाय उसकी कमजोरी का संकेत बन जाता है। बजट सत्र के लगातार दिनों तक बाधित रहने से आम जनता के मुद्दे, आर्थिक नीतियों पर चर्चा और विकास से जुड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं। कांग्रेस, जो स्वयं को लोकतंत्र की प्रहरी बताती है, यदि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती दिखे, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई असाधारण बात नहीं है। संसदीय इतिहास में यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है। लेकिन इस कदम का औचित्य तभी बनता है, जब यह संसदीय मयार्दा और ठोस तर्कों के साथ उठाया जाए। मौजूदा मामले में विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। यदि यह सच है, तो इसका समाधान भी संसदीय संवाद और नियमों के तहत होना चाहिए। सदन के भीतर नारेबाजी, वेल में आकर हंगामा और बार-बार कार्यवाही ठप कराना, किसी भी तरह से समाधान नहीं है।

कांग्रेस का रवैया यहां विरोध से अधिक टकराव का नजर आता है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर पूरा

सत्र बाधित करना, जबकि देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा लंबित हो, यह दशार्ता है कि पार्टी प्राथमिकताओं को लेकर भ्रमित है। लोकतंत्र में व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है। संसद किसी एक नेता का मंच नहीं, बल्कि 140 करोड़ नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधि सदन है। यदि किसी नेता को बोलने में आपत्ति है, तो उसके लिए नियम, अध्यक्ष और संसदीय समितियां मौजूद हैं। सत्र को ही ठप कर देना, लोकतांत्रिक दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक हठधर्मिता है।

कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब वह सत्ता में रही, तब विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप उस पर भी लगे। ऐसे में आज नैतिक ऊंचाई का दावा करना, बिना आत्मालोचना के, खोखला लगता है। संसदीय परंपराएं दोतरफा जिम्मेदारी मांगती हैं। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखे। हाथ जोड़कर बजट पर चर्चा की अपील करना किसी मंत्री की कमजोरी नहीं, बल्कि संसदीय परंपरा को बचाने का प्रयास है। इसके बावजूद हंगामा जारी रहना, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है।

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति अस्पष्ट दिखती है। एक ओर प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, दूसरी ओर प्रमुख नेता खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। यह दोहरा संदेश पार्टी की आंतरिक असमंजस को दशार्ता है। यदि स्पीकर सचमुच पक्षपात कर रहे हैं, तो पार्टी को एकजुट और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन यहां यह कदम अधिक प्रतीकात्मक विरोध जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है। संसद में महिला सांसदों के साथ हुई घटनाओं, बैनर और पोस्टर की राजनीति, और पुस्तक विवाद जैसे मुद्दों को जिस तरह तूल दिया गया, उसने मूल प्रश्नों को हाशिए पर धकेल दिया। देश महंगाई, रोजगार, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट बहस चाहता है। लेकिन कांग्रेस का फोकस बार-बार ऐसे विवादों पर रहा, जिनसे सदन का समय नष्ट हुआ। यह रवैया न तो विपक्ष की परिपक्वता दिखाता है और न ही लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता।

लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन रचनात्मक विरोध उससे भी अधिक जरूरी है। कांग्रेस यदि सचमुच जनता की आवाज बनना चाहती है, तो उसे सड़क की राजनीति को संसद के भीतर दोहराने से बचना होगा। संसद संवाद का मंच है, संघर्ष का नहीं। यहां तर्क, तथ्य और नीति से सरकार को घेरा जाता है, न कि शोर और अवरोध से। हर बार सदन ठप कर देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे न तो जनता का भरोसा बढ़ता है और न ही लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं।

अंततः सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या हारा, बल्कि यह है कि संसद चली या नहीं। बजट सत्र का समय अमूल्य होता है। इसे बाधित कर कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार को, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाया है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता को असहज करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। इसके लिए सदन का चलना अनिवार्य है। यदि कांग्रेस इस मूल सिद्धांत को नहीं समझती, तो उसका विरोध लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि अवरोधकारी राजनीति के रूप में ही देखा जाएगा।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसान का पहलू

अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से भारत के श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो हानिकारक बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में भारत से ट्रेड डील होने का एलान किया। कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत पर ह्यलिबरेशन डे टैरिफह्ल को 25 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देगा। बदले में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका से व्यापार में टैरिफ एवं गैर-टैरिफ रुकावटों को शून्य कर देगा, और 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला एवं अन्य उत्पाद खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर का अर्थ भारत के सालाना बजट का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा (तकरीबन 46 लाख करोड़ रुपये) है। बहरहाल, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह उल्लेख किया कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अब सिर्फ 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इससे ट्रेड डील को लेकर फिर से अस्पष्टता बन गई। बहरहाल, यह साफ है कि इस डील को हासिल करने के लिए भारत ने आगे बढ़ कर कई बड़ी रियायतें दी हैं। उनमें से कई तो करार के पहले ही दे दी गईं। इनमें अमेरिका के कृषि, वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु एवं केमिकल्स उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क में भारी कटौती शामिल है। साथ ही रक्षा सौदों का दायरा बढ़ाया गया। परमाणु उत्तरदायित्व कानून में अमेरिकी कंपनियों के अनुकूल बदलाव किया गया। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने रूस से तेल की खरीदारी घटाई, ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं। अब अगर ये पहलू ट्रेड डील का हिस्सा है, तो यह बेहद आपत्तिजनक बात होगी। इसलिए कि यह अपने संप्रभु निर्णय को किसी अन्य देश की भू-राजनीतिक जरूरतों के सामने समर्पित करने जैसा होगा। दरअसल, खरीदारियों के बारे में भी कोई व्यक्ति या देश अपनी जरूरत एवं बाजार के तर्कों से फैसला लेता है। किसी दबाव में आकर इस बारे में बंधना अपने हितों से समझौता होगा। अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से वस्त्र, जेवरात आदि जैसे श्रम-केंद्रित उद्योगों को राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू-राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें ट्रेड डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो नुकसान का पहलू होगा।

चिंतन-मनन

दुखी चित्त के लक्षण हैं उत्सव

दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। भौतिकवादी और आध्यात्मवादी में एक ही फर्क है। आध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है। क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा। क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी न बचा, पुराने को देखने वाला भी न बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण हैं। चित्त दुखी है वर्ष भर, एकाध दिन हम उत्सव मना कर खुश हो लेते हैं। वह खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है। क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है? दिन! अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था, तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हां, खुशी का भ्रम पैदा करुंगा। दीये, पटाके, फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुश हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी हैं, तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी यह सोचा न होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। चौबीस घंटे मनोरंजन चाहिए, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। हम समझते है कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है, बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है। और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए हैं। पुराने पड़ गए चित्त में, जिसमें धूल ही धूल जम गई है; वह नए दिन, नया साल, इन सबको ईजाद करता है। और धोखा पैदा करता है थोड़ी देर। कितनी देर नया टिकता है? कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर जैसे झाड़ देना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को। उससे कुछ होने वाला नहीं है।

पं .दीनदयाल उपाध्याय सच्चे अर्थों में भारतीयता के जीवंत प्रतीक थे

मुकेश तिवारी

विलक्षण प्रतिभा के धनी दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर 1916 को उत्तर प्रदेश के ग्राम नगला चन्द्र भान में हुआ था।हालकि परिवारिक कारणों से उनका बचपन अपने नाना चुन्नीलाल के घर ग्राम धनकिया में बीता। जब नाना नौकरी छोड़कर गुडकी मंडई आ गए तो वे भी अपने नाना के साथ

गुडकी मंड ई आ गए।हालांकि दिनदयाल जी के 9वर्ष की आयु पूरी होने के बाबजूद उनके अध्ययन की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी अत वे अपने मामा राधारमण के पास आ गए जो गगापुर में रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे।

?गंगा पुर आने के पश्चात ही उनकी सुचारू रुप से शिक्षा प्रारंभ हो सकी।गंगा पुर में वे चार सालों तक रहे।कयोकि गंगापुर में इससे आगे पढाई की व्यवस्था नहीं थी।ऐसी स्थिति में 2 जून 1929 को कोटा के एक स्कूल में दखिला लेना पडा। वे यहाँ सेल्फ सपोटिग हाउस में रहते थे।कक्षा 5 से 7 तक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उतीर्ण की। इसके पश्चात उन्हें राजगढ़ आना पडा।

उन्होंने 8 वी कक्षा के राजगढ़ में दखिला लिया। 8 वी कक्षा मेंछऔठट शानदार अकों से उतीर्ण होकर जब वो 9 वी कक्षा में गए तो उनकी कबलियत के चलते 10 वी कक्ष के छात्र उनसे गणित के सवाल हल करवाने के लिए उनके पास आते थे। सीकर के कल्याण स्कूल से 10 की परीक्षा प्रथम श्रेणी श्रेणी से उतीर्ण करने के पश्चात 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में वे सवप्रथम रहे। तत्कालीन सीकर के महाराज कल्याण सिंह ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया 10 रुपए माहवार छात्रवृत्ति और पुस्तक एवं आदि के लिए 250 रुपए की राशि पारितोषिक के रूप में दी गई । उन दोनों पिलानी उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था । दीनदयाल इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1935 में पिलानी चले गए 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में प्रथम रहे सभी विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए । बिरला कॉलेज के वे प्रथम छात्र थे जिसने इतने सम्मानजनक अकों में परीक्षा पास की थी। सीकर महाराज के समान ही घनश्याम दास बिड़ला ने एक स्वर्ण पदक 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति तथा पुस्तक आदि के खर्चे के लिए 250 रुपए प्रदान किए।

इसी वर्ष बीए की पढ़ाई के लिए कानपुर गए यह रामा मंडी में किराए के मकान में रहे। 2 वर्ष तक यहां रहकर 1941 में मात्र 25 बर्ष की आयु में बीटी करने के लिए प्रयाग चले गए। 25वर्ष की आयु तक दीनदयाल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कम से कम ग्यारह स्थानो पर कुछ समय तक रहे।इसके साथ ही उनका प्रवेश , सार्वजनिक जीवन में हो गया है!

कानपुर में अध्ययन करते समय अपने सहपाठी कालू जी महाशब्दे के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए।कानपुर में ही पहली बार उनकी संघ संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार जी से मुलाकात हुई।बाबा साहेब आपटे के दादा राव परमार्थ इनके छात्रावास में ठहरा करते थे। उनकी इस दौरान अनेक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वीर सावरकर के कानपुर प्रवास के दौरान उन्हे शाखा में आमंत्रित करके उनसे बौद्धिक वर्ग करवाया।कानपुर के सुन्दर भंडारी भी दीनदयाल जी के सहपाठी थे।

संघ के शारीरिक कार्यक्रम को दीनदयाल जी भले ही ठीक तरह से नहीं कर पाते थे लेकिन बौद्धिक परीक्षा में सदैव अव्वल रहते थे।वे सच्चे अर्थों में भारतीयता के जीवंत प्रतीक और एक परिपूर्ण मानव थे। पंडित जी एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी थे जिन्होंने राजनीति में रहते हुए अपने वतन की सेवा के व्रत के परायण में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964को ग्वालियर में भारतीय जनसंघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन में एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत दिया ,वह जीवन के सभी सुखो का मूल मंत्र है ।यह भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय विचार का आज के युग के लिए अनुकूल समुच्चय है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा ।यह सिद्धांत समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कार्य करने का है ।पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखता है।

पंडित दीनदयाल का जिक्र करते ही , पंडित जी की जो छवि हमारी आंखों के सामने उभरती है वह किसी बड़े राजनीतिक दल के कद्दावर नेता की नहीं बल्कि एक सहृदय अग्रज.आत्मीय मित्र.और मार्गदर्शक की है.हिन्दुस्तान भर के लाखों अनुयाई पं दीनदयाल को इस स्वरूप में अपने साथ पाते थे.आज हमारे मुल्क में राजनीति का जो स्वरूप हमें द्रष्टिगोचर होता है और उसमें राजनीति करते हुए तमाम सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हमें मिलते हैं उनकी तुलना यदि दीनदयाल उपाध्याय के साथ करें तो हमें बेहद आश्चर्य होता है हमारे जहन में विचार आता है कि इस आपाधापी के दौर में भी हमें ऐसी शख्सियत का मार्गदर्शन मिला।

कालांतर में पंडित दीनदयाल जो अमूल्य विचार हमें प्रदान कर गए.वह न केवल इस कीर्ति की आत्मा और शरीर दोनों के ही अनुकूल था.प्रसिद्धि से दूर.अहंकार से रहित और निश्छल मुस्कुराहट वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसी ही शख्सियतों में से एक थे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने नाम के अनुरूप ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने व्यक्ति, परिवार,समाज, और देश को समग्र परिवेश में देखा, पंडित उपाध्याय जी के बाल्यकाल में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठा गया था, फलत बचपन के उन सुहाने दिनों से वंचित हो गए ,जब खेलने और खाने की जगह उन्हें अभावों में जीना पड़ा,यही वजह थी, कि बचपन में ही कठिन परिस्थितियों से संघर्ष की और व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद जीवन में उन्होंने संघर्ष से कभी मुंह नहीं मोड़ा,

एम ए उतरार्द्ध की परीक्षा नहीं दे सके, मामा जी के अनुरोध करने पर वे प्रशासनिक परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण हुए और साक्षात्कार में भी वे चुन लिए गए ।उनकी अध्ययनशीलता सार्वजनिक जीवन में जाने के पश्चात प्रखरतम होती चली गई ,कालांतर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति ने जो जीवन उभरा वह उनका ऋषि व्यक्तित्व था,वे ताउम्र अविवाहित रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे राजनीतिक क्षेत्र में गए और भारतीय जन संघ के महामंत्री बने ,उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मुझे दो दीनदयाल जी मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का मानचित्र बदल के रख दूंगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना के दो वर्ष भी पूर्ण नहीं हो पाए थे काश्मीर आंदोलन के दौरान 23जून को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया, आजाद भारत के नवगठित राजनीतिक दल का भार पूर्ण तौर पर 36 वर्षीय दीनदयाल उपाध्याय जी के कंधे पर आ गया,वे निरंतर17 सालों तक भारतीय जन संघ के महामंत्री रहे और 18 में बर्ष में जन संघ के अध्यक्ष बने लेकिन नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया, दीनदयाल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था, वे सामान्य व्यक्ति,सक्रिय कार्यकर्ता कुशल संगठक, प्रभावी नेता एवं विचारक थे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञानी एवं दार्शनिक एव अच्छे वक्ता थे। किसी भी विषय पर अच्छी प्रकार से अभ्यास और विभिन्न कोणों से उस पर विचार व्यक्त करने के उपरांत ही अपना कोई मत व्यक्त करते थे ,उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक कुछ उदाहरणों से पता चलती है, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति पर दीन दयाल जी के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है। उनका चिंतन आज भी प्रासंगिक है राष्ट्र एक स्थाई सच है,राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्य पैदा होता है, राष्ट्र का संगठन के निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उत्पन्न नहीं होता है ,एक राष्ट्र भाव की विस्मृति के कारण घटक शिथिल पड़ते हैं और यदि पूरी तरह निष्क्रिय हो गए, तो संपूर्ण राष्ट्र के विनाश का कारण भी बनते हैं, अतः हमें कालजेय स्थाई सक्षम, आत्मनिर्भर व्यवहारिकता और स्वाभाविक संगठन के लिए राष्ट्र को आधार मानना होगा, राष्ट्र का संगठन दृढ़ हुआ तो सामर्थ निर्माण होगा और विभिन्न अंग पुष्ट हो सकेंगे ,राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए धर्म का संरक्षण करते हुए आना चाहिए, यह संघटित कार्प शक्ति एवं पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मक वादी है। टुकड़ों में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से उचित हो सकता है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह कतई उपयुक्त नहीं है पश्चिम की समस्या का मुख्य कारण उसका जीवन के संबंध में सतही ढंग से विचार करना है। दीनदयाल जी का मानना था कि स्वराज प्राप्त करते ही हम स्व की भावना विस्मित कर बैठे तथा विदेशी विचारधारा हमारे आकर्षण और अनुकरण का केंद्र बन गई। आज आवश्यकता है कि अपने स्व का परिचय किया जाए, बिना उसके स्वराज का कोई अर्थ नहीं है स्वतंत्रता हमारे विकास और सुख का साधन मात्र नहीं बन सकती जब तक हमें अपनी हकीकत का पता नहीं तब तक हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता और ना ही उसका विकास ही संभव है,हम स्वर की भावना किस मत कर बैठे हैं विदेशी विचारधारा मारे आकर्षण और अनुकरण का केंद्र बन गई आज आवश्यकता है कि अपने स्व का परिचय किया जाये कर विनाश के स्वराज का कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्रता हमारे विकास और सुख का साधन नहीं बन सकती जब तक हमें अपनी हकीकत का पता नहीं तब तक हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता और नहीं उसका विकास ही संभव है।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

विपक्ष के 128 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि उन्होंने नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ह्यबोलने की इजाजत नहीं देनेह्ल, साथ ही कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया है।लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य कई सांसद नोटिस सौंपने वालो में शामिल है।लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार, विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 (1) से नियम 198 (5) तक के तहत पूरी की जाती है।इस प्रक्रिया के तहत नियम 198 (1) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिये सदन की अनुमति लेनी पड़ती है।सदन की अनुमति के लिए नियम 198 (1) (ख) के मुताबिक, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है।नियम 198 (2) के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं।नियम 198 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है।नियम 198 (4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन लोकसभाध्यक्ष वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है।नियम 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।अब तक लोक सभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं।लोक सभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जे बी कृपलानी ने पेश किया था। लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे।लेकिन सन 1978 में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था।अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गये थे।इसके अलावा पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गाँधी सरकार और दूसरी बार पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी दो बार सन1996 व सन1998 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गये थे।सन 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था। लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप हैं कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सांसदों को बोलने का मौका कम देते हैं।हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। संसद के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है।

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। जब भी विपक्ष को सरकार या फिर लोकसभाध्यक्ष पर भरोसा नहीं होता है तो उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लाया जाता है, इसे मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है।इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वोटिंग में बहुमत मिलने पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार सन1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता विग्नेश्वर मिसिर ये प्रस्ताव लाए थे।इस प्रस्ताव पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को जवाहर लाल नेहरू ने सदन की गरिमा का सवाल बताया था।

सन1954 के बाद लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव सन 1966 में लाया गया।लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव था।वहीं तीसरी बार सन1987 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था।पिछले तमाम प्रस्तावों की तरह ये अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था।अब देखना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कितना चल पाता है।इससे लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी जाती है या फिर यह प्रस्ताव धड़ाम गिरता है।फिलहाल तो संख्या बल देखते हुए ऐसा नही लगता कि ओम बिरला की कुर्सी जाएगी,बाकी आने वाला वक्त बताएगा।

(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

ड्रोन तकनीक से रोजगार के नए विकल्प मिले

तकनीक के इस आधुनिक युग में ड्रोन अब केवल मनोरंजन या वीडियो शूटिंग का साधन नहीं रह गया है। यह अब कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का माध्यम बन चुका है। भारत में ड्रोन तकनीक के तेजी से विस्तार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। सरकार की 'ड्रोन शक्ति योजना' और 'मेक इन इंडिया' पहल ने इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार दोनों को प्रोत्साहित किया है। आज देश के कई उद्योग ड्रोन विशेषज्ञों और प्रशिक्षित पायलटों की तलाश में हैं, जिससे युवाओं के लिए हजारों नौकरियों के द्वार खुल रहे हैं।

ड्रोन का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। किसान अब खेतों की निगरानी, फसलों की सेहत का विश्लेषण, कीटनाशक छिड़काव और सिंचाई प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार भी 'कृषि ड्रोन योजना' के तहत युवाओं को सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ताकि वे ड्रोन ऑपरेटर के रूप में काम कर सकें। यह न केवल किसानों की उत्पादकता बढ़ा रहा है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का नया साधन बन रहा है।

ड्रोन तकनीक का दूसरा बड़ा उपयोग सर्वेक्षण और मैपिंग में हो रहा है। सड़क, रेलवे, रियल एस्टेट, खनन और शहरी विकास परियोजनाओं में ड्रोन की मदद से सटीक डेटा और 3डी मैपिंग तैयार की जाती है। इससे इंजीनियरिंग और सर्वे एजेंसियों को विशेषज्ञ ड्रोन ऑपरेटरों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह, आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाढ़, भूकंप या आग जैसी स्थिति में ड्रोन की मदद से प्रभावित इलाकों की रीयल-टाइम जानकारी मिलती है, जिससे राहत दलों को समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

फिल्म और मीडिया उद्योग में भी ड्रोन ने नई दिशा दी है। अब फिल्मों, विज्ञापनों, और लाइव इवेंट्स की हवाई शूटिंग के लिए प्रशिक्षित ड्रोन कैमरा ऑपरेटरों की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस विभाग और रक्षा संगठन सीमाओं, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बड़े आयोजनों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे युवाओं को टेक्निकल सपोर्ट और सर्विलांस ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिल रही है।

ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी ड्रोन डिलीवरी सेवाओं पर प्रयोग कर रही हैं। आने वाले वर्षों में दवाओं, दस्तावेजों और छोटे सामानों की डिलीवरी ड्रोन के जरिए की जाएगी, जिससे ड्रोन पायलट, मेंटेनेंस इंजीनियर और रूट मैनेजर जैसे नए पद सृजित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में 2030 तक ड्रोन उद्योग एक लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की बढ़ रही मांग

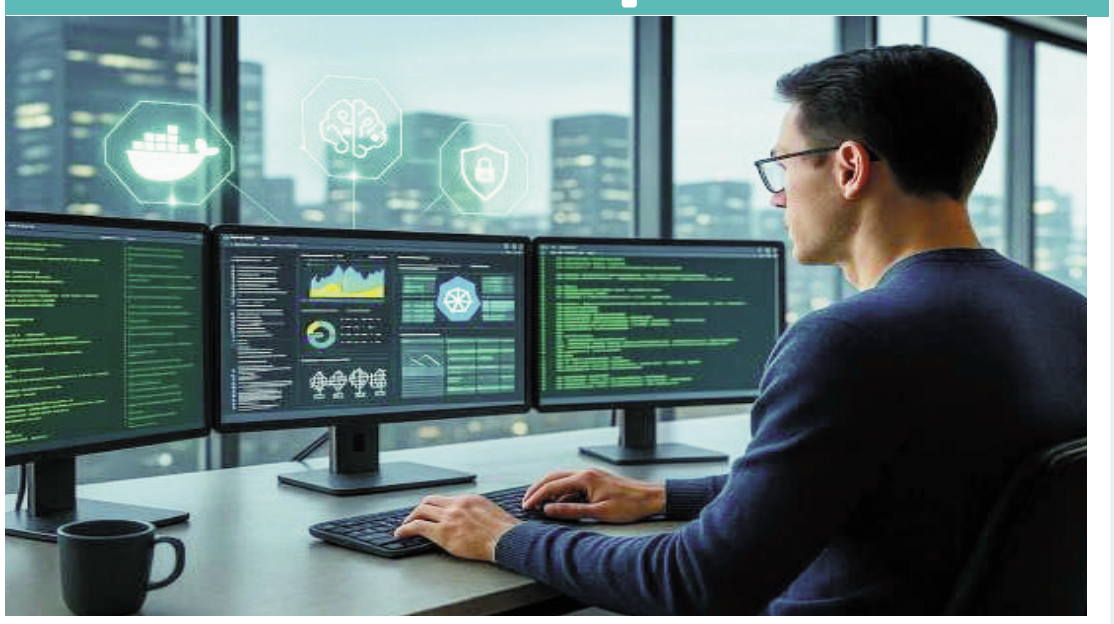

सूचना तकनीक के इस दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों तक को होती है। यह पेशेवरों क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों तक को होती है। यह पेशेवरों क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है। यही वजह है कि इन पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग में बेहतर करियर बना सकते हैं। इसमें कौशल बढ़ाने के लिए आप पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न क्लाउड आधारित कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने से आपको जेमिनी, जेनरेटिव एआई को समझने और स्ट्रीमलिट के साथ एप्लीकेशन बनाने का मौका मिलेगा।

क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग

डेटा और प्रोग्रामिंग को दूरस्थ रूप से संग्रहीत और एक्सेस करने का एक तरीका है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर जानकारी होस्ट करने के बजाय इंटरनेट का उपयोग करता है। संक्षेप में, क्लाउड कंप्यूटिंग को डेवलपर्स और गैर-डेवलपर्स दोनों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्लाउड और ऑन-प्रिमाइसेस डेटा को कनेक्ट और साझा करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग को मूल रूप से एक डिलीवरी पद्धति के रूप में सोचें। एस प्रकार से यह डेटा स्टोरेज भी है।

इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल

शुरूआती स्तर पर यह माइक्रो-लर्निंग कोर्स आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल की छोटी-छोटी बारीकियों के बारे में बताएगा। इस कोर्स में एलएलएम के उपयोग और इसके प्रदर्शन को अच्छा बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में ऐसे गूगल टूल्स भी शामिल किए गए हैं। जिनकी मदद से आप खुद का जेनरेटिव एप बना सकेंगे।

प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई

प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई कोर्स में जेनरेटिव एआई आउटपुट कंट्रोल करने, प्रॉम्प्ट तैयार करने और वास्तविक दुनिया के मार्केटिंग परिदृश्यों में जेमिनी मॉडल लागू करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सिखाया जाता है।

जेन एआई एप विथ जेमिनी और स्ट्रीमलिट

जेन एआई एप विथ जेमिनी और स्ट्रीमलिट आपको पायथन एसडीके, टेक्स्ट जेनरेशन और जेमिनी एपीआई के साथ कार्यात्मक निर्णय लेने और क्लाउड रन के साथ स्ट्रीमलिट एप्लिकेशन बनाने का तरीका सीखाएगा।

इमेज जेनरेशन

पिछले कुछ सालों में अनुसंधान और उद्योग और दोनों ही क्षेत्रों में डिफ्यूजन मॉडल कॉफी लोकप्रिया हो रहा है। इस कोर्स के जरिए आपको डिफ्यूजन मॉडल के सिद्धांतों को वर्टेक्स एआई के साथ जोड़कर सीखने से कौशल निखरेंगे।

मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस ऑन वर्टेक्स : इसमें आपको मशीन लर्निंग के समाधान के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा।

बीबीए या बीसीए के साथ लॉ करें

समय के साथ ही करियर विकल्प भी बदलते जा रहे हैं। अब छात्रों के पास एक ही फील्ड में कई करियर विकल्प होते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेस का चलन बढ़ा है। इन कोर्सेस में दो अलग-अलग डिग्रियों की पढ़ाई एक साथ होती है। कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट को दोनों की मिलाकर एक डिग्री दी जाती है। अगर आप बीबीए या बीसीए के साथ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जानिए कुछ बेस्ट ऑप्शन.

बीबीए, बीसीए लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच साल)

बीबीए एलएलबी : इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई एक साथ होती है। इसमें बिजनेस से जुड़े विषयों (मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर) के साथ-साथ कानून के मूल सिद्धांत (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ) पढ़ाए जाते हैं।

बीबीए और बीसीए के बाद लॉ (3 साल का एलएलबी)

बीबीए या बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो पहले बिजनेस या टेक्नोलॉजी में बेस बनाना चाहते हैं और फिर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं।

बीबीए के बाद: कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ में विशेषज्ञता ले सकते हैं।

बीसीए के बाद: साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में करियर बना सकते हैं।

स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स

बीबीए/बीसीए के साथ या बाद में आप लॉ से जुड़े शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे :

1- साइबर लॉ (बीसीए के लिए)

2- कॉर्पोरेट लॉ (बीबीए के लिए)

3- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर)

यह कोर्स 6 महीने से 1 साल के हो सकते हैं और ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं.

लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन इस प्रकार मिलेगा

बीबीए एलएलबी के लिए

एलिजिबिलिटी: 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से), कम से कम 45-50 फीसदी अंकों के साथ. कुछ कॉलेज में मैथ्स होना अनिवार्य हो सकता है.

प्रवेश परीक्षा

कलेट टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए.

एआई एलईटी

एलऐट प्राइवेट लॉ कॉलेज के लिए.

एमसी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए.

प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही कालेजों में प्रवेश मिलेगा।

जनरल मेडिसिन की ओर बढ़ा रुझान

मेडिकल क्षेत्र में पिछले कुछ साल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल ग्रेजुएट्स अब सर्जरी की जगह पर एमडी जनरल मेडिसिन कारना चाहते है। मास्टर इन सर्जरी के (एमएस) में प्रवेश में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। टॉप 100 में से सिर्फ तीन उम्मीदवारों ने ही एमएस को चुना है जबकि 2021 में कम से कम 11 उम्मीदवारों ने एमएस कोर्स चुना।

एआई का डर

इसी तरह रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में एमडी, जो कभी टॉप रैंकर्स के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कोर्स थे, उनमें दिलचस्पी में भारी गिरावट देखी गई है। कैंडिडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आने को लेकर परेशान हैं, जिसके रेडियोलॉजी में डॉक्टरों की जगह लेने का डर है। डर्मेटोलॉजी में आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में हालिया बढ़ोतरी ने मेडिकल ग्रेजुएट्स की दिलचस्पी बदल दी है। जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और न्यूरोसर्जरी जैसी सर्जिकल ब्रांच में दिलचस्पी बहुत ज्यादा सीखने पढ़ने, काम के बोझ, मेडिको-लीगल रिस्क, इमरजेंसी अधिक होना और वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी की वजह से कम हुई है।

मेडिसिन सबसे बड़ी वरीयता

पिछले पांच सालों में टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों के बीच सीट प्रेफरेंस पैटर्न में काफी बदलाव आया है। लगभग 44-47 फीसदी ग्रेजुएट्स मेडिसिन और 40-43 फीसदी रेडियोलॉजी चुन रहे हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी में काम के लंबे घंटे होते हैं। डॉक्टर अपने क्लिनिक खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बहुत कम होती है क्योंकि ज्यादातर सर्जिकल काम के लिए हॉस्पिटल से अटैचमेंट की जरूरत होती है। सर्जरी सेक्टर सीमित है क्योंकि सीनियर स्पेशलिस्ट के रिटायर होने तक नए लोगों के लिए कम जगह बची है। जब तक वे रिटायर नहीं होते, नए डॉक्टरों के लिए मौके कम होते हैं।और पूरे कोर्स के दौरान हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है।

ह्यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट में अच्छे अवसर

निजी क्षेत्र में आजकल सेल्स, ब्रैंड मैनेजमेंट या मार्केट रिसर्च में काफी संभावनाएं हैं हालांकि इसके लिए आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) काफी बेहतर होनी चाहिए। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये विकल्प मौजूद हैं

ह्यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों पर पूरे ऑफिस के लोगों का मैनेजमेंट होता है। इसके लिए आपके पास अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी तरह बात करने की क्षमता और रिश्ते बनाने की कला का होना बेहद जरूरी है।

स्पेशलाइज्ड एमबीए

कुछ इंस्टिट्यूस प्लेसमेंट्स को ध्यान में रखकर कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टेलिकॉम मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, फॉरिन ट्रेड हैं।

इस तरह के हैं कोर्स में एमबीए में दो साल की डिग्री के अलावा, एक साल का फुल टाइम प्रोग्राम, पार्ट टाइम एमबीए, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए जैसे विकल्प हैं हालांकि हर विषय की अपनी-अपनी खूबी और खामियां हैं।

ऑपरेशंस मैनेजमेंट

अगर आप विपरीत परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और तकनीक में आपकी रुचि है, तो आप यह स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यह क्वॉलिटी कंट्रोल और प्रॉडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में अहम भूमिका निभाता है।

फाइनैंस

ये लोग बैक एंड पर काम करते हैं और इंवेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस वगैरह की रीढ़ की हड्डी होते हैं।

सिस्टम मैनेजमेंट

यह स्पेशलाइजेशन आईटी से ताल्लुक रखता है और अच्छी टेक्निकल व बिजनेस समझ रखने वालों के लिए यह बेहतर रहता है। इसके बाद आपको सिस्टम कंसल्टेंसी, अकाउंट या प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में प्लेसमेंट मिल सकता है।

स्वत्वाधिकार प्रकाशन एवं मुद्रक राजकुमार आमेटा के लिए स्मार्ट कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिन्टर्स, कोर्ट के सामने, माण्डलगढ़ से प्रकाशित एवं मुद्रित। मो. 9649222850 Email.smarthalchalnews@gmail.com